

- 1930 : महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे।
- 1949 : भारत स्काउट एण्ड गाइड की स्थापना हुई।
- 1964 : नौसेना ने पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया।
- 1975 : सउदी अरब के राजा फैजल की हत्या।
- 1979 : देश का पहला नौसेना संग्रहालय मुम्बई में खुला।
- 1993 : मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या भारती की रहस्यमय तरीके से मौत।
- 2002 : भारत, म्यांमार व थाइलैंड के बीच मोरे-कलावा-मांडले सड़क परियोजना पूरी करने हेतु सहमति।

पूरे किए जा रहे सभी चुनावी वादे : हेमंत

झारखंड में वायुसेना का पहला एयर शो रांची में 19 एवं 20 अप्रैल को

झारखंड मुक्ति मोर्चा के 46वें स्थापना दिवस पर हजारीबाग में हुआ भव्य कार्यक्रम

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

हजारीबाग। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46वां स्थापना दिवस शुक्रवार को हजारीबाग जिला स्कूल मैदान में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत मंत्री योगेंद्र महतो और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनु शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यक्रमों को संगठन मजबूत करने का मंत्र दिया। साथ ही 2029 के चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारी करने का आह्वान किया।

हजारीबाग की धरती झानुगो के लिए उर्वरक: सीएन

इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह झानुगो का संगठनात्मक कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जल, जंगल और जमीन बचाने और राज्य के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए ही झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया गया था। राज्य गठन में कई आंदोलनकारी शहीद भी हो गए। बहुत संघर्ष के बाद राज्य बना है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह अभी से ही चुनाव की तैयारी में लग जाएं और पार्टी को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की नींव होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हजारीबाग की धरती पार्टी के लिए बहुत ही उर्वरक है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चुनाव के दौरान जो भी वादे किए गए थे, वह सभी वादे पूरे किए जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान और आधी आबादी को



पैर पर खड़ा किया जा रहा है। सरहुल त्योहार में जिस तरह से लोगों ने हिस्सा लिया इससे यह स्पष्ट है कि उनके पॉकेट में पैसे थे, तभी त्योहार का रंग भी झारखंड वासियों के चेहरे पर चढ़ा। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक ग्रामीणों पर खर्च किए जा रहे हैं। अगर गांव मजबूत होगा, तभी प्रखंड मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि सीएम उक्तुष्ट विद्यालय छात्रों को बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहा है। 9000 क्षमता वाले स्कूल में 35000 से अधिक फॉर्म भरे गए हैं। जो यह बताता है कि प्राइवेट स्कूलों के बजाय अभिभावक अब

ओर पिछली भाजपा की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 16 साल तक राज्य में शासन किया। उनके कार्यकाल में राज्यवासियों पर जुल्म किए गए। लोगों को राशन नहीं दिया गया और जमीन लूट ली गई। यही नहीं कई स्कूल बंद कर दिए गए। अपने 30 मिनट के भाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना काल से लेकर अपने जेल जाने की बातों को साझा किया। उन्होंने कहा कि झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। देश के पहले मुख्यमंत्री को झूठा आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया। झूठा आरोप कभी सच नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर बाहर रहते तो एक भी सीट भाजपा को नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि पांच सालों तक भाजपा के लोग सरकार को गिराने की कोशिश करती रही। लेकिन जनता के प्यार के कारण सरकार ने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया। कोरोना काल के दौरान परिवार की मुखिया का जो दायित्व होता है, वह पूरा किया गया। उन्होंने मंच से दोबारा सरकार बनाने के लिए राज्य की जनता का आभार जताया।

शांति के साथ रागवणमी नवावे की अपील

इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से रामनवमी का पर्व शांति और सौहार्द से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई जगह खुराफाती लोग ज्यादा संख्या में हैं। वे लोग हो-हल्ला ज्यादा करते हैं। उन लोगों को अपने आसपास के लोगों से बचा कर रखना है।



नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

रांची। झारखंड में भारतीय वायुसेना (एयरफोर्स) का पहला एयर शो राजधानी रांची में 19 और 20 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री से उनके कार्यालय कक्ष में आज भारतीय वायुसेना की टीम ने मुलाकात की। भारतीय वायुसेना की टीम ने उपायुक्त से रांची में सूर्य किरण एकोबैटिक टीम द्वारा किए जानेवाले एयर शो को लेकर विस्तृत चर्चा की। डीसी ने टीम को आश्वासन दिया कि उन्हें जिला प्रशासन हर संभव मदद देगा। झारखंड में होनेवाला भारतीय वायुसेना का यह पहला एयर शो होगा। सूर्यकिरण टीम द्वारा 19 और 20 अप्रैल 2025 को रांची में प्रस्तावित खोजा टोली आर्मी ग्राउंड में एयर शो का प्रदर्शन किया जाएगा। एयर शो के मुख्य कार्यक्रम से पूर्व 17 अप्रैल 2025 को एयर शो के मुख्य कार्यक्रम से पहले इसका फुल ड्रेस रिहर्सल किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने उपायुक्त से एयर शो में होने वाली गतिविधियों और इसकी तैयारी से संबंधित जानकारी साझा की। उपायुक्त ने वायु सेना की टीम को आश्वासन दिया कि रांची जिला प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता की जाएगी। इसके साथ ही सभी तरह की प्रशासनिक तैयारी, एयर शो से संबंधित व्यापक प्रचार प्रसार, तकनीकी सहयोग आदि के लिए जिला प्रशासन ने वायु सेवा की टीम को आश्वासन दिया। बैठक में भारतीय वायुसेना की ओर से विंग कमांडर पीके सिंह और स्क्वाड्रन लीडर वालिया एवं जिला के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

नहीं रहे 'भारत कुमार' रामनवमी पर तमिलनाडु में कई योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

मुंबई। अभिनेता एवं निर्देशक मनोज कुमार का शुक्रवार सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। वे 87 साल के थे। वे विशेष रूप से अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे। उन्हें 'भारत कुमार' के नाम से भी जाना जाता था। उम्रकार, पूरब-परिचय, क्रांति, रोटी-कपड़ा और मकान उनकी बेहद कामयाब फिल्में रहीं। उनका अंतिम संस्कार आज सुबह 11 बजे मुंबई के पवनहंस स्मशान घाट पर होगा। मनोज कुमार का भी समय से लिबर सिरोसिस से जूझ रहे थे। उन्हें 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2016 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से नवाजा गया।

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के अवसर पर तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इस अवसर पर वे भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, नए पम्बन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और इस पुल से ट्रेन और जहाज को रवाना करेंगे तथा पुल के संचालन का अवलोकन करेंगे। इसके बाद लगभग 12:45 बजे वे रामेश्वरम के रामनाथस्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। लगभग 1:30 बजे रामेश्वरम में प्रधानमंत्री विभिन रेलवे और सड़क परियोजनाओं का नींव पत्थर रखेंगे और 8,300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की इन परियोजनाओं को देश के नाम समर्पित करेंगे। इस अवसर

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पर प्रधानमंत्री संबोधन भी देंगे। प्रधानमंत्री नए पम्बन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और रामेश्वरम-तम्बयम (चेन्नई) नई ट्रेन सेवा की शुरुआत करेंगे। यह पुल गहरी सांस्कृतिक महत्व रखता है। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के निकट धनुकोडी से प्रारंभ हुआ था।

नया पम्बन रेलवे ब्रिज :

रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला यह पुल भारतीय इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। इसकी निर्माण लागत 550 करोड़ रुपये से अधिक है। यह पुल 2.08 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 99 स्तंभ हैं और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पान है, जो 17 मीटर तक उठता है, जिससे जहाजों का

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

आवश्यकता कम होती है। इसे भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए द्विआयामी रेल पटरियों के लिए डिजाइन किया गया है। विशेष पॉलिसिलॉक्सने कोटिंग इसे जंग से बचाती है, जिससे यह कठोर समुद्री पर्यावरण में भी लंबे समय तक टिकाऊ रहता है।

प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन और नींव पत्थर रखने वाली परियोजनाएं :

प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की विभिन्न रेलवे और सड़क परियोजनाओं का नींव पत्थर रखेंगे और उन्हें देश के नाम समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में शामिल हैं :

- एनएच- 40 के वालाजपेट- रणपेट खंड का 4-लेन निर्माण (28 किमी)
- एनएच- 32 के पूडियकुप्पम-सत्तानाथपुरम खंड का निर्माण (57 किमी)
- एनएच- 36 के चोलापुरम- थंजालूरु खंड का निर्माण (48 किमी)
- एनएच- 32 के पूडियकुप्पम-सत्तानाथपुरम खंड का निर्माण (57 किमी)
- एनएच- 36 के चोलापुरम- थंजालूरु खंड का निर्माण (48 किमी)
- एनएच- 40 के वालाजपेट- रणपेट खंड का 4-लेन निर्माण (28 किमी)
- एनएच- 332 के विलुपुरम- बदावा मिलेगा।

रांची में रामनवमी से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

रांची। रांची में रामनवमी पर शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए रांची पुलिस अलर्ट है। रामनवमी से पहले आज (4 अप्रैल) विभिन्न इलाकों में ड्रोन से घरों की छतों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जुलूस के रूट और विभिन्न मार्गों का औचक निरीक्षण किया। मेन रोड, हिंदपीढ़ी और डेली मार्केट इलाके में ड्रोन कैमरे से घरों की छतों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान घरों की छतों की जांच की गयी कि कहीं किसी छत पर झूट-पत्थर न रखा हो। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा ने पूरे इलाके का जायजा लेने और संवेदनशील जगहों पर जवानों की

घरों की छतों का ड्रोन से निरीक्षण



तैनाती करने का आदेश दिया। एसएसपी ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर किसी इलाके में किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उक्त थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जायेगी। रांची उपायुक्त ने कहा कि जुलूस के मार्ग पर भारी संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस बलों की

दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक की मौत

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

भागलपुर (नबिटा ब्यूरो)। भागलपुर में सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। पूरा मामला नवगछिया के रंगरा थाना अंतर्गत दुमरिया पुल के पास का है, जहां तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर अनियंत्रित हुई और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रैक्टर के सामने एक अन्य वाहन आ रहा था, जिसे बचाने के क्रम में यह घटना हुई और ट्रैक्टर सीधे खाई में जा गिरा, जिससे चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गोपालपुर थाना अंतर्गत कालूचक का रहने वाला संजय दास के रूप में हुई है। चालक संजय दास नवगछिया दुमरिया चरघट पंचायत के पूर्व प्रखंड प्रमुख और वर्तमान मुखिया मनकेश्वर सिंह उर्फ मंटू सिंह का गाड़ी चलाया करता था।

सोशल मीडिया पर बच्चों के बैन की याचिका खारिज

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगरस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा- यह नीतिगत मामला है। आप संसद से कानून बनाने के लिए कहें। यह हमारे दायरे से बाहर है। हालांकि कोर्ट ने अन्य अर्थोर्टी के सामने अपील करने की छूट दी है। पीठ ने कहा कि आठ स्पटाह के भीतर कानून के अनुसार अपील की जा सकती है। जेप फाउंडेशन की याचिका में केंद्र सरकार और अन्य अर्थोर्टी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक बच्चों की पहुंच को रेगुलेट करने के लिए बायोमेट्रिक वैरिफिकेशन जैसा एज वैरिफिकेशन सिस्टम शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसके अलावा बाल संरक्षण नियमों का पालन करने में असफल रहने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई थी। अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने

के लिए अपने पेरेंट्स की सहमति लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर चुका है। इस ड्राफ्ट को लोगों के लिए 3 जनवरी को जारी किया गया था। लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से विचार किया जा रहा है। ड्राफ्ट सामने आने के कुछ दिन बाद पेरेंट की सहमति के प्रावधान का एक मॉडल भी सामने आया था। आईटी मिनिस्ट्री के सूत्रों ने बताया था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पेरेंट्स के मोबाइल फोन और ईमेल पर अंटीपी आ जाएगा। ये अंटीपी डिजिटल स्पेस में पहले से मौजूद बच्चों और पेरेंट्स की डिजिटल आईडी कार्ड के आधार पर जनरेट होगा। इसके जरिए बच्चों या माता पिता का डेटा पब्लिक नहीं होगा। उम्र और कंफर्म की परमिशन भी पेरेंट से ली जा सकेगी। सूत्रों के मुताबिक पेरेंट की परमिशन हमेशा के लिए नहीं होगी। उन्हें जब लॉग कि उनकी परमिशन का गलत यूज हो रहा है या वे परमिशन थोड़े से ली गई है, परमिशन के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में वे परमिशन वापस भी ले सकेंगे।

रिश्वत लेते रंगे हाथ धराया दारोगा

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

रांची। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज एसीबी ने रांची में बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो रांची की टीम ने नामकुम थाने के दारोगा चंद्रदीप प्रसाद को 30 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित आशीष कुमार यादव ने इस बाबत एसीबी रांची में शिकायत की थी। यूपी के बलिया के रहनेवाले आशीष कुमार यादव ने एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी), रांची में शिकायत की कि 18 नवंबर 2023 को नंदजी यादव (आम घाट, बलिया) की पुत्री नीतू कुमारी से परिवादी का छेका हुआ था, लेकिन निजी कारणों से छेका टूट गया। पंचों के जरिए दिए गए सामान का आदान-प्रदान हो गया। इसके बावजूद नंदजी यादव द्वारा रांची के नामकुम थाने में उनके और उनके परिजनों के खिलाफ दहेज प्रतिबंध

राहुल गांधी को लखनऊ हाईकोर्ट से झटका

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

लखनऊ। राहुल गांधी की याचिका लखनऊ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने वीर सावरकर मानहानि मामले में लखनऊ की सेशन कोर्ट के समन आदेश और 200 रुपए जुर्माने को लेकर हाईकोर्ट में 2 अप्रैल को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उन्हें अल्टरनेट रेमेडी (वैकल्पिक उपाय) अपनाने का सुझाव देते हुए लखनऊ सेशन कोर्ट जाने को कहा है। दरअसल, 3 मार्च को लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर राहुल गांधी पर 200 रुपए जुर्माना लगाया था। उन्होंने एसीबी में इसकी शिकायत की। इसके बाद एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन किया। फिर कार्रवाई के लिए जाल बिछाया और दारोगा चंद्रदीप प्रसाद 30 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ दबोका गया।



अनुसार, राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' और 'पेंशन लेने वाला' कहा था। शिकायतकर्ता ने कहा- यह बयान समाज में वैमनस्य और घृणा तारीख को भी पेश नहीं होते हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गैर-जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है। शिकायतकर्ता गुंफें पांडेय के

FOR REGISTRATION : ISO, TRADE MARK, PATENT

DESIGN AND COPYRIGHT, ATTORNEY

GLOBAL VISION

(A Complete Solution in Professional Services)

: Regd. Office/ Head Office :
Manaitand, Near Water Tank
Dhanbad, Jharkhand- 826001
Command Office : Jagat Trade Centre, Patna

Contact No.- 9835333441, 8210823092

E-Mail : globalvision96@yahoo.in

वक्फ संशोधन बिल पारित होते ही अल्पसंख्यकों का सीएम से मोहभंग

नवबिहार टाइम्स संवाददाता
पटना। बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जारी सियासी उबाल ने अब जेडीयू की जड़ों को भी हिलाना शुरू कर दिया है। वक्फ बिल पर मोदी सरकार को समर्थन देने के बाद जदयू में अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच गहरी नाराजगी देखी जा रही है। अब मुजफ्फरपुर जिले से इस नाराजगी का पहला बड़ा असर सामने आया है, जहां जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अफरीदी रहमान ने अपने 20 से अधिक समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही अफरीदी रहमान और उनके समर्थकों ने अपने-अपने घरों पर लगे जेडीयू के नेमप्लेट तोड़कर विरोध जताया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पार्टी से नाता तोड़ते हुए इन नेताओं ने नीतीश कुमार पर मुसलमानों के साथ विश्वासघात करने का गंभीर आरोप लगाया है। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में पार्टी से अलग हुए नेताओं में मो.

पार्टी में बढ़ता असंतोष, मुस्लिम नेताओं में नाराजगी

इमरान अली, मो. आजाद अली, मो. शमीम रहमान, मो. अबूल, राजू खान, मो. इम्तियाज, जानीसर खान, मो. छोटू, मो. अहमद, मो. विकी, रऊफ अंसारी और दानिश इकबाल सहित कई कार्यकर्ता शामिल हैं। अफरीदी रहमान ने इस्तीफा देते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियां हमारे पूर्वजों की धरोहर हैं। इन संपत्तियों में मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा जैसी आस्थाओं से जुड़ी चीजें आती हैं, जिन्हें आजादी से पहले वक्फ किया गया था। लेकिन केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लाकर मुसलमानों की इन संपत्तियों को हड़पने की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि जेडीयू जैसे धर्मनिरपेक्ष कहे जाने वाले दल का इस बिल का समर्थन करना मुस्लिमों के साथ खुला धोखा है। अफरीदी रहमान ने कहा कि उन्होंने वर्षों तक जेडीयू का झंडा उठाया, लोगों के बीच पार्टी की विचारधारा का प्रचार किया। लेकिन अब वह

साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है कि हमने इतनी वफादारी निभाई और अंत में हमें ही धोखा मिला। यह घटनाक्रम केवल मुजफ्फरपुर तक सीमित नहीं है। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के रुख से मुस्लिम समुदाय के नेताओं में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। पार्टी से जुड़े कई अन्य जिलों के मुस्लिम कार्यकर्ता भी अपने-अपने स्तर पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में अन्य जिलों से भी इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो सकता है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध किया जा रहा है। समुदाय का आरोप है कि यह बिल मुस्लिमों की धार्मिक संपत्तियों को छीने का रास्ता खोलता है। हालांकि केंद्र सरकार इसे सुधार बता रही है, लेकिन विपक्ष में शामिल कई पार्टियों के साथ जेडीयू, लोजपा, हम पार्टी और दक्षिण भारत के कुछ दलों द्वारा समर्थन देने के बाद से अल्पसंख्यकों में असंतोष गहरा गया है।

पुलिस रात्रि गश्ती दल पर गोलीबारी

चौकीदार जख्मी, महकमे में मची खलबली

नवबिहार टाइम्स संवाददाता
सहरसा। जिले में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। जिले के बसनही थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात गश्ती पर निकली पुलिस टीम पर अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस घटना में थाने में पदस्थानित ग्रामीण चौकीदार राजेंद्र पासवान को गोली लग गई, जिन्हें पहले सहरसा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर गंभीर स्थिति देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद जिले भर में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सहरसा एसपी और कई थानों की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और इलाके में सघन छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। घटना को लेकर घायल चौकीदार राजेंद्र पासवान ने बताया कि वह थानाध्यक्ष कुलवंत कुमार के साथ रात्रि गश्ती पर थे। वे डेमजमाल संधाल टोला के पास पहुंचे ही

थे कि सामने से आ रही एक बाइक पर सवार कुछ सदिग्ध युवकों को रोका गया। पुलिस को देखते ही उन लोगों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से इलाका दहल उठा। अपराधियों ने दो राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक गोली चौकीदार राजेंद्र पासवान को बांह में लगी। घटना के बाद साथी पुलिसकर्मीयों ने उन्हें तुरंत सहरसा सदर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने बताया कि गोली उनके हाथ में अभी भी फंसी हुई है, जिस कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना को लेकर मुख्यालय डीएसपी कमलेश्वरी प्रसाद सिंह ने बताया कि पुलिस ने गश्ती के दौरान एक अपराधी को पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अपराधी ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में चौकीदार घायल हो गया और इसी बीच आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। डीएसपी ने बताया कि इस वादात के बाद पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी है और संभावित ठिकानों पर लगातार छापामारी की जा रही है। एसपी स्वयं बसनही पहुंचे हैं और मामले की निगरानी कर रहे हैं।

छठ के दौरान गंगा नहाने में डूबा 12 वर्षीय बालक

नवबिहार टाइम्स संवाददाता
हाजीपुर। छठ महापर्व की आस्था उस समय मातम में बदल गई जब वैशाली जिले के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के शिवनगर स्थित काशी घाट पर गंगा नदी में दर्दनाक हादसा हो गया। जहां शुरुवार सुबह नहाते समय 12 वर्षीय स्वराज कुमार उर्फ सौरभ कुमार की डूबने से मौत हो गई। उस समय स्वराज अपनी दादी और परिवार के साथ छठ पूजा के अवसर पर घाट पर गया था। जानकारों के अनुसार, मृतक स्वराज कुमार स्थानीय निवासी हरबंस मिश्रा का पुत्र था। छठ पूजा के अवसर पर उसकी दादी और परिवार के अन्य सदस्य घाट पर पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। इस दौरान स्वराज भी गंगा में स्नान कर रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। घटना होते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल नदी में खोजबीन शुरू की और कड़ी मशकत के बाद स्वराज के शव को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किशोर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही गांव में मातम पसर गया। मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है, खासकर उसकी दादी जो छठ पूजा करने घाट पर आई थीं, सधमें हैं। बच्चे की मौत ने पूरे परिवार की खुशियों को गम में बदल दिया। इधर, घटना की सूचना मिलते ही जुड़ावनपुर थाना अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थाना अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली, पुलिस टीम को तत्काल मौके पर भेजा

गया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि वह एक दुर्घटनावादी हुई मृत्यु है। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर छठ पूजा के दौरान घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। अग्नि पीड़ितों के बीच सहायता राशि का वितरण शिवाजीनगर। प्रखंड के रहियार उत्तर पंचायत वार्ड एक गुलराही गांव में हुए अगलागी घटना के बाद अंचल कार्यालय में सभी पीड़ित परिवार को सीओ वीणा भारती ने सहायता राशि का चेक दिया। पीड़ित परिवार गोडी यादव, चुनचुन देवी, योगानंद यादव, रूपा देवी, शांति देवी, राजेंद्र यादव, देव चंद्र यादव, लुखी देवी, को चेक दिया गया। बीते गुरुवार को गुलराही गांव में अचानक अग लगने से घर के अंदर रखे मोटरसाइकिल सहित सभी सामान जलकर राख हो गया था। मौके पर पंचायत मुखिया गजेंद्र प्रसाद साहद अंचल कर्मचौजूद थे।

अपने पैतृक गांव पहुंचे मनोज वाजपेयी



नवबिहार टाइम्स संवाददाता
गौनाहा। फिल्मी दुनिया और महानगरीय जीवनशैली से पांच दिनों का अवकाश लेकर अपने पैतृक गांव बेलवा पहुंचे अभिनेता मनोज वाजपेयी शुक्रवार को गौनाहा प्रखंड में बेलसंडी पंचायत के गम्हरिया गांव के ग्रामीणों से मिले। ग्रामीणों से गांगुली नदी के कटाव की विनाशालीला सुनकर वे भावुक हो गए। नदी के तट पर पहुंचे, जहां हर साल बरसात में किसानों की जमीन और ग्रामीणों के सपने का दर्दनाक गांगुली नदी करती है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नदी का कटाव नहीं, ग्रामीणों के सुनहरे भविष्य पर वज्रपात है। अगर समय रहते तोस कदम नहीं उठाए गए, तो गांव और किसान दोनों ही नक्शे से गायब हो जाएंगे। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मैं कटाव से निजात के लिए डीएम समेत अन्य अधिकारियों से बात करूंगा और जरूरत पड़ी तो इसके लिए संघर्ष भी करूँगा। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्मी

दुनिया से अलग, वह मेरी असली दुनिया है। सो, मेरा फर्ज भी है कि मैं इस सामाजिक संकट में अपना योगदान दूँ। मनोज वाजपेयी के साथ राजनीतिज्ञ सह समाजसेवी शैलेन्द्र प्रताप सिंह, शिक्षाविद ज्ञानदेव देव मणि त्रिपाठी, राकेश राव, नितेश राव, दीपेन्द्र वाजपेयी भी थे। पंचायत बाजपेयी ने सभी के साथ चर्चा के बाद अपने वालों समय में समाधान की दिशा में टोस प्रयास का भरोसा दिलाया। उल्लेखनीय है कि बरसात के दिनों में गांगुली नदी में बाढ़ और कटाव इलाके की बड़ी समस्या है। वर्ष 2024 के बाद में लगभग आधा दर्जन घर नदी में खिलीन हो गए थे। बाढ़ पीड़ित भुवाली महतो, बच्चा गुरो, कमलेश गुरो, मनोज महतो, सुरेंद्र काजी ने कहा कि कटाव हर साल जारी रहता है। नदी से हजारों एकड़ फसल बर्बाद जाती है। गांव और किसानों की जमीन को बचाने के लिए मजबूत बांध बनवाने की जरूरत है।

प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने विस अध्यक्ष से की शिष्टाचार मुलाकात

कई मुद्दों पर भी हुई चर्चा

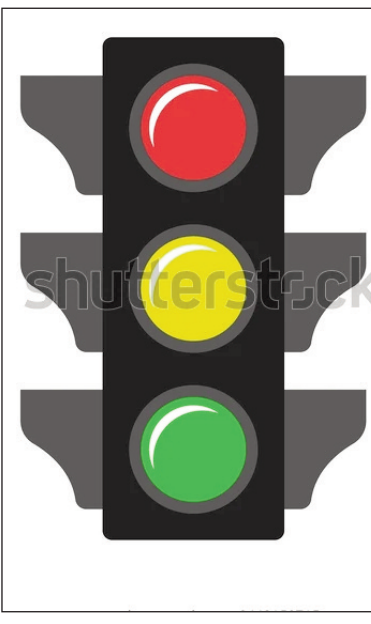
नवबिहार टाइम्स संवाददाता
टुंडी। पूर्वी टुंडी प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष योगेश प्रसाद राजक आज गुरुवार देर शाम पार्टी के निर्देश पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से उनके नाला स्थित निवास स्थान पर गुलदस्ता भेंट कर शिष्टाचार भेंट किया एवं अपने क्षेत्रों की ज्वलंत मुद्दों को लेकर विचार-विमर्श किया। ज्ञात हो कि जिला कांग्रेस के निर्देश पर विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर पूर्वी टुंडी प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने एक तीर से कई निशान साधने में सफल हुए हैं। उनके इस मुलाकात से बाजारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दबी जुबान लोग कह रहे हैं कि वर्तमान प्रखंड अध्यक्ष की आलाकमान ने कोई बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। उन्होंने मीडिया को बताया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने



बल पर एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरेगी तथा तथा कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को सम्मान का खयाल रखने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। विदित हो कि विधानसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट कर खासे उत्साहित हैं श्री राजक तथा पूर्वी टुंडी समेत सभी क्षेत्रों में कांग्रेस आने वाले दिनों में एक सशक्त रूप से मजबूत होने की बातें दुहराई।

अब जहानाबाद में ट्रैफिक की होगी डिजिटल निगरानी

नवबिहार टाइम्स संवाददाता
जहानाबाद। आने वाले दिनों में जहानाबाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बदलने वाली है। अब शहर के प्रमुख चौकों पर पटना की तर्ज पर रेड, येलो और ग्रीन ट्रैफिक लाइट लगाई जाएंगी। रेड लाइट का मतलब होगा रुकना, ग्रीन लाइट आगे बढ़ने की अनुमति देगी, और येलो लाइट झुंझवरो को चेतावनी देगी कि वे धीमे हो जाएं क्योंकि रेड लाइट आने वाली है। ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए शहर के प्रमुख चौकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की मदद से वाहनों के नंबर प्लेट की तस्वीर ली जाएगी और जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा, उसे ऑटोमेटिक तरीके से ई-चालान जारी किया जाएगा। यह सिस्टम खासतौर पर ओवरस्पीडिंग और रेड लाइट जंप करने जैसी गलतियों पर नजर रखेगा। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्रमुख स्थानों को पहचान कर ली है। काको मोड़, अरवल मोड़ और अबैकवर चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का प्रस्ताव पहले ही दिया जा चुका है।



फिलहाल, सड़कों के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसके पूरा होते ही इन स्थानों पर ट्रैफिक

सिग्नल और सीसीटीवी कैमरों की स्थापना का काम शुरू कर दिया जाएगा। खासकर काको मोड़ और अरवल मोड़ के पास कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को ट्रैक किया जा सके। अभी तक ट्रैफिक पुलिस इन चौकों पर मैनुअली ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, जिससे कई वाहन चालक चालान से बच निकलते हैं। लेकिन ई-चालान सिस्टम लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। इससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। खासकर, बाइक सवारों के लिए हेलमेट न पहनने जैसी लापरवाहियों पर भी निगरानी रखी जाएगी। ट्रैफिक डीएसपी नवीन कुमार ने बताया कि इस प्रस्ताव को जनवरी में पेश किया गया था, लेकिन सड़कों के चौड़ीकरण के कारण इसका कार्यान्वयन रुका हुआ है। वहीं, रात्रि परिवहन पदाधिकारी राहुल कुमार ने भी आश्वासन दिया है कि ई-चालान सिस्टम जल्द शुरू किया जाएगा। यह नया कदम जहानाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और अनुशासित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

397 जूनियर इंजीनियरों की पदस्थापना से पटना मेट्रो के कार्यों को मिलेगी गति

▶ 1350 नए पदों का हुआ सृजन ▶ 15 अगस्त से चालू होने की संभावना

नवबिहार टाइम्स संवाददाता
पटना। राज्य के नगर निकायों में चल रही शहरी योजनाओं में अब तेजी आएगी। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने 397 जूनियर इंजीनियरों को विभिन्न नगर निकायों, बुडको, बिहार आवास बोर्ड, पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में पदस्थापित किया है। इन अभियंताओं को शहरी इलाकों में चल रही विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को समसम गुणवत्तापूर्ण तरीके से लागू करने का निर्देश दिया गया है। पटना मेट्रो के कार्यों को गति देने के लिए भी विभाग ने 11 सिविल, जबकि चार-पांच इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियरों की तैनाती है। पटना मेट्रो के प्रायॉरिटी कॉरिडोर को इसी साल 15 अगस्त तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि 397 अभियंताओं के पदस्थापन से संप्रदात अशोक भवन, प्रशासनिक भवन, जल जीवन हरियाली मिशन जैसी योजनाओं के काम में और तेजी आएगी। बिहार सरकार के इस बड़े कदम से जन निकायों, सड़क, नाला, पेयजल आपूर्ति, भवन निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार होगा। शहरी नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ भी मिल सकेंगी। जूनियर इंजीनियरों की बहाली बिहार तकनीक सेवा आयोग द्वारा की गई है। अधिसूचना के मुताबिक इलेक्ट्रिकल शाखा से 12 जेई और मैकेनिकल शाखा से 35 जेई का पदस्थापन किया गया है। साथ ही सिविल शाखा से 350 कर्नल अभियंताओं को पदस्थापित किया गया है।

सभी अभियंताओं को एक सप्ताह के अंदर नव पदस्थापित कार्यालय में शैक्षणिक योग्यता एवं आवासीय समेत अन्य जरूरी प्रमाणों के साथ योगदान करने का आदेश दिया गया है। दूसरी ओर राज्य के सभी 38 जिले, अरवल मोड़ वाले शहरों के सुनिश्चित विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने आयोगना क्षेत्र प्राधिकार में 1350 नए पद सृजित किए हैं। इसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, नगर निवेशक, सार्वजनिक पदाधिकारी जैसे पद शामिल हैं। विभाग के अनुसार, अगले बीस सालों की संभावित आबादी को देखते हुए शहरों का मास्टर प्लान तैयार

की जा रहा है। इसमें विभिन्न भूमि उपयोग (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक इत्यादि) मूलभूत सुविधाओं एवं सड़क निर्माण को योजना का विस्तृत वर्णन होगा। राज्य के प्रमुख शहरों में टाउनशिप परिचयोजना लाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में प्रमण्डलीय जिला मुख्यालय एवं अन्य जिला मुख्यालय के आधार पर वर्गीकृत करते हुए पदों की स्वीकृति दी गई है। प्रमण्डलीय स्तर के नौ जिला मुख्यालय वाले आयोगना क्षेत्र प्राधिकार में प्रति आयोगना प्राधिकार के लिए 39 पद, जबकि अन्य 29 जिला मुख्यालय वाले आयोगना प्राधिकार में प्रति आयोगना प्राधिकार के लिए 34 पद स्वीकृत किए गए हैं। पदों के अलावा जीआईएस विशेषज्ञ, आईटी मैनेजर, डाटा इंटी ऑर्परेटर, मल्टी टास्किंग स्टाफ की सेवा बल्लूना या विभाग की ओर से निर्धारित एजेंसी के जरिए ली जाएगी।

मगही संस्कृति का संगम होगा मगही 'महोत्सव'

नवबिहार टाइम्स संवाददाता
पटना। मगघ की सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से पांच अप्रैल 2025 को बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग स्थित बापू टावर में मगही महोत्सव 2025 का आयोजन होने जा रहा है। यह एक दिवसीय भव्य कार्यक्रम सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक चलेगा और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। यह आयोजन न केवल मगही भाषा और लोक परंपरा के संरक्षण का प्रयास है, बल्कि युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी माध्यम है। महोत्सव को मगघ सभ्रात अशोक की जयंती के अवसर पर खास तौर से आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव की शुरुआत सुबह 9:00 बजे प्रतिभांगियों के गंजीकरण से होगी। इसके तुरंत बाद मगघ की परंपरागत गाथा घरानों की दुमरी गायकों से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। प्रख्यात गायक राज सिन्धुआर की प्रस्तुति सुबह 10:15 बजे से 11:00 बजे तक होगी, जो संगीत प्रेमियों को मगघ की सुरमयी संस्कृति से जोड़ देगी। महोत्सव में पूरे दिन पर मगही भाषा, इतिहास, पुरातत्व, उद्यमिता, सिनेमा और लोक संस्कृति पर केंद्रित सत्र आयोजित होंगे। इनमें बिहार और देश के नामी विद्वान, इतिहासकार, उद्यमी और कलाकार हिस्सा लेंगे। मगही



संपादकीय

रूस से कच्चा तेल खरीदना अब हो सकता है मुश्किल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद विश्व राजनीति में धमकी की नई परंपरा कायम करने पर तुले हैं। अब उन्होंने रूस से कच्चा तेल खरीदने वालों को धमकाया है कि जो ऐसा करेगा, वह अमेरिका में कारोबार नहीं कर पाएगा। ऐसे देशों पर पच्चीस से पचास फीसद तक अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। यह धमकी उन्होंने इसलिए दी है कि रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की दिशा में न तो रूस और न ही यूक्रेन ने अपेक्षित सहयोग का रुख दिखाया है। इससे ट्रंप निराश हैं। पिछले महीने

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की को बुला कर ट्रंप ने कड़े शब्दों में फटकार लगाई थी। यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी गई है। इससे उम्मीद बनी थी कि रूस, अमेरिका की युद्ध विराम संबंधी शर्तें मान जाएगा, मगर उसने अपनी शर्तें रख दी कि सभी नाटो देश यूक्रेन को सैन्य मदद और गोपनीय सूचनाओं पर रोक लगाएँ, तभी वह युद्ध विराम पर विचार कर सकता है। पहले ईरान और खाड़ी देशों से खरीदता था, मगर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भारतीय तेल कंपनियों

में ट्रंप ने अब रूस पर नकेल कसने का रास्ता चुना है। मगर यह रास्ता भी उनके लिए कितना आसान और कारगर साबित होगा, कहना मुश्किल है। अमेरिका की नई धमकी से भारत की चिंता जरूर कुछ बढ़ गई है, क्योंकि सचमुच अगर वह ऐसा करता है, तो भारत की तेल कंपनियों के लिए रूस से तेल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। अभी भारत सबसे अधिक कच्चा तेल रूस से खरीदता है। पहले ईरान और खाड़ी देशों से खरीदता था, मगर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भारतीय तेल कंपनियों

ने वहां से तेल खरीदना बंद करके रूस से खरीदना शुरू कर दिया था। इस तरह कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से महंगाई तेजी से बढ़ेगी, जिसका अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हालांकि भारतीय तेल कंपनियाँ अभी समझ नहीं पा रही हैं कि अमेरिका का अतिरिक्त शुल्क लगाने का ढांचा क्या होगा, इसलिए वे इसे अधिक चिंता का विषय नहीं मान रही हैं, पर जिस तरह पहले ही पारस्परिक शुल्क नीति के तहत अमेरिका ने भारी शुल्क थोप दिए हैं, उससे भारत के लिए संतुलन बिठाना

कठिन हो रहा है। यह नया शुल्क और परेशान करने वाला साबित हो सकता है। मगर ट्रंप प्रशासन के लिए भी अपनी शुल्क नीति पर लंबे समय तक कायम रह पाना कठिन होगा। इसे लेकर अमेरिका में ही विरोध हो रहा है। इसलिए कि पारस्परिक शुल्क के चलते अमेरिकी कारोबार पर भी बुरा असर पड़ सकता है। जिन चीजों के लिए अमेरिका दूसरे देशों पर निर्भर है, उनकी कीमतें बढ़ेंगी, तो वहां भी महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में अमेरिकी लोगों का विरोध लंबे समय तक सहन कर पाना ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा। वहां के मध्यावधि चुनाव में ट्रंप की पार्टी के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिर यह भी कि ट्रंप के नए ऐलान से रूस कितने दबाव में आ पाएगा, कहना मुश्किल है।

संघ की कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका विक्रमा को दिए इंटरव्यू में होसबाले ने साफ कर दिया कि उस समय यानी 1984 में विश्व हिंदू परिषद और साधु-संतों ने तीन मंदिरों की बात की थी। इसलिए अगर संघ के स्वयंसेवक इन मंदिरों के लिए काम करना चाहते हैं, तो हम उनको रोकेंगे नहीं। साफ है, इस बयान के बाद इन मथुरा-काशी दोनों स्थलों से जुड़े विवाद और इनके आंदोलनों को एक नई ऊर्जा, इन मंदिरों के जीर्णोद्धार, स्वतंत्र अस्तित्व हासिल करने में सफलता मिलेगी। इससे एक बार फिर भाजपा की ताकत बढ़ेगी एवं हिन्दुओं को एकजुट करने का वातावरण बनेगा। बिहार में कुछ ही माह बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और साल

मथुरा-काशी से जुड़ी नई मुहिम का आह्वान

(ललित गर्ग)
दत्तात्रेय होसबाले का यह साक्षात्कार महत्वपूर्ण होने के साथ दूरगामी सोच से जुड़ा है। हालांकि, होसबाले ने अपने इसी इंटरव्यू में देश की सभी मस्जिदों को मुद्दा बनाने की प्रवृत्ति को सामाजिक ताने-बाने के लिए नुकसानदेह बताकर संतुलन साधने की कोशिश की है।

हिंदू समूहों का दावा है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मथुरा में श्रीकृष्ण मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करके उनके ऊपर मस्जिदें बना दीं। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद और साधु-संतों ने 1984 में तीन मंदिरों की बात की थी, जिनमें में अयोध्या में श्रीराम मन्दिर बन चुका है। इसके बाद कई लोगों को लगने लगा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उसके अन्य सहयोगी संगठन इससे संतुष्ट हो चुके हैं और काशी व मथुरा के विषय को जैसे उन्होंने त्याग दिया है या भूला दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोकसभा में वक्फ विधेयक के पेश किए जाने से कुछ ही घंटे पहले संघ के सरकार्यवाह एवं महामंत्री दत्तात्रेय होसबाले ने काशी ज्ञानवापी और मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े आंदोलनों-कार्यक्रमों में संघ के स्वयंसेवकों को न रोकने की बात कह कर एक नई मुहिम के आह्वान का अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दे दिया है, जिसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ हैं। पिछले कुछ समय से इनको लेकर एक ऊहापोह की स्थिति थी, लेकिन संघ के इस मुद्दे पर छाने धूंधलको को हटाते हुए अपने नये बयान से ऊर्जा का संचार किया है। भले ही इससे राजनीति गर्माये, लेकिन हिन्दू आस्था को इससे खुशी मिली है।

संघ की कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका विक्रमा को दिए इंटरव्यू में होसबाले ने साफ कर दिया कि उस समय यानी 1984 में विश्व हिंदू परिषद और साधु-संतों ने तीन मंदिरों की बात की थी। इसलिए अगर संघ के स्वयंसेवक इन मंदिरों के लिए काम करना चाहते हैं, तो हम उनको रोकेंगे नहीं। साफ है, इस बयान के बाद इन मथुरा-काशी दोनों स्थलों से जुड़े विवाद और इनके आंदोलनों को एक नई ऊर्जा, इन मंदिरों के जीर्णोद्धार, स्वतंत्र अस्तित्व हासिल करने में सफलता मिलेगी। इससे एक बार फिर भाजपा की ताकत बढ़ेगी एवं हिन्दुओं को एकजुट करने का वातावरण बनेगा। बिहार में कुछ ही माह बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और साल 2027 की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। बिहार एवं उत्तर प्रदेश दोनों ही प्रदेशों में जातिगत गणना और आरक्षण का बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिशें

हो रही हैं। इन दोनों चुनावों में काशी और मथुरा बड़ा मुद्दा बने, तो कोई आश्चर्य नहीं है। दोनों मन्दिर बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के दो छोरों पर स्थित हिंदुओं के दो बड़े पवित्र एवं पावन धर्मस्थल हैं। मथुरा में श्रीकृष्ण मंदिर भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के रूप में हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण आस्था-स्थल हैं, जहाँ लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं। दोनों मंदिर हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और करोड़ों भक्तों को आकर्षित करते हैं, दोनों मंदिर भारतीय संस्कृति और इतिहास का अहम हिस्सा हैं और उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं।



काशी में विश्वनाथ और मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर का पुनरुद्धार केवल भौतिक संरचनाओं को पुनर्सथापित करने का प्रयास नहीं है-यह भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सार को पुनर्जीवित करने एवं आहत हिन्दू आस्था पर मरहम लगाने का आह्वान है। सनातन धर्म की शाश्वत विरासत के प्रतीक ये मंदिर आक्रमणकारियों के सदियों के हमलों के बावजूद हिंदुओं की दृढ़ता और भक्ति के प्रमाण हैं। इन पवित्र स्थलों को पुनः प्राप्त करना हमारे पूर्वजों के बलिदान का सम्मान करने, हमारी विरासत को संरक्षित करने और हमारी समृद्ध परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने का कार्य है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू मंदिरों के बारे में सच्चाई सबके सामने है, लेकिन ये मामले अनसुलझे हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के ये स्थल लंबी अदालती लड़ाई के बावजूद अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। दत्तात्रेय होसबाले का यह साक्षात्कार महत्वपूर्ण

होने के साथ दूरगामी सोच से जुड़ा है। हालांकि, होसबाले ने अपने इसी इंटरव्यू में देश की सभी मस्जिदों को मुद्दा बनाने की प्रवृत्ति को सामाजिक ताने-बाने के लिए नुकसानदेह बताकर संतुलन साधने की कोशिश की है। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशना सही नहीं है। भले ही पिछले साल दिसंबर में मस्जिदों को लेकर उठ रहे विवाद को शांत करने का उन्होंने यह प्रयास किया था। लेकिन काशी और मथुरा भी उसमें शामिल रहे हो, ऐसा कैसे सोचा जा सकता है? होसबाले ने इस साक्षात्कार में गौ हत्या, लव जिहाद और धर्मतराण जैसी चिंताओं को स्वीकार किया। उन्होंने अस्पृश्यता यानी छुआछूत

होसबाले के बोल से जहाँ हिन्दू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा को बल मिला है, वहीं राष्ट्रीयता भी मजबूत होती हुई दिख रही है। संघ की स्थापना भी इसी उद्देश्य एवं राष्ट्रवादी आंदोलन को एक मजबूत सांस्कृतिक आधार देने के लिए की गई थी। हमारी सदियों पुरानी प्राचीन सभ्यताएं जो धर्म, अहिंसा और भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित थीं उपनिवेशवाद के शोर में अपनी आवाज खो न जाये, हिन्दू समाज पर रह-रह हो रहे हमले रूके, 2047 तक सनातन संस्कृति को सत्य कचलने के प्रयास विराम पाये-इन जटिल स्थितियों में भारत के लोगों को एक सांस्कृतिक छत्र के नीचे एकजुट करने की दृष्टि से होसबाले ने जगाया है, चेताया है, संगठित होने का आह्वान किया है। निश्चित तौर पर इन दोनों मंदिर मुद्दों को नए सिरे से हवा देने की इस कवायद ने संघ विरोधियों एवं मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों के सामने एक नई गंभीर चुनौती पेश की है। खासकर यह देखते हुए कि अयोध्या की रणनीतिक सफलता ने हिंदुत्व की राजनीति का आधार मजबूत किया है, हिन्दुओं को संगठित किया है।

मंदिर-मस्जिद विवाद के बीच संघ की तरफ से पहले भी कई बयान आते रहे हैं। ये बयान दर्शाते हैं कि संघ भले ही सीधे-सीधे विवाद से खुद को भले ही अलग रखता हो, वैचारिक रूप से वह इनको पूरा समर्थन देता है। संघ का समर्थन देश को अराजक बनाने का कभी नहीं रहा, उसके सामने बड़ा लक्ष्य देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का भी है। बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों में भारत-विरोधी शक्तियाँ नए सिरे से सक्रिय होने लगी हैं, उनसे लड़ने की ताकत एवं रणनीति भी संघ चाहता है। संघ सामंजस्यपूर्ण और संगठित भारत के आदर्श को आकार देने के लिये प्रतिबद्ध है। श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति जैसे आंदोलनों ने भारत के सभी वर्गों और क्षेत्रों को सांस्कृतिक रूप से संगठित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सीमा सुरक्षा, शासन में सहभागिता से लेकर ग्रामीण विकास तक, राष्ट्रीय जीवन का कोई भी पहलू संघ के स्वयंसेवकों से अछूता नहीं है। सी वर्षों की संघ यात्रा हिन्दू एकता, विश्व शांति व समृद्धि के साथ सामंजस्यपूर्ण और एकजुट भारत के भविष्य के संकल्प के साथ-साथ काशी-मथुरा के मुद्दे से भी जुड़ी है। हिंदुओं को बचाने और उन्हें सम्मान और गरिमा के साथ देश सेवा में तत्पर करने के लिये उनकी आस्था एवं अस्तित्व पर लगे धावों को तो भरना ही होगा। लेखक, पत्रकार, स्तंभकार, (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

दिल्ली या यूपी, कौन मारेगा बाजी

दिल्ली एक बार फिर दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। इसके कुछ दिन बाद आई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट भी यही बता रही है कि बीती सदियों में दिल्ली सबसे प्रदूषित महानगरों में रही। 40 दिन तक तो हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में रही।

(अक्षय शुक्ला)
महानगरों के प्रदूषण से बचने के लिए लोग पहलुओं का रुख करते हैं, पर अब तो वो भी इससे अछूते नहीं रहे। वायु गुणवत्ता पर निगरानी रखने वाली स्विस् कंपनी आईक्यू एयर की हालिया रिपोर्ट की मानें तो मेघालय का बर्नीहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। उच्च इरॉन और पारदर्शी नदियों वाले पूर्वोत्तर के इस खूबसूरत राज्य का नाम सबसे खराब हवा के मामले में अब्जल आना चौकाने वाला है।

सवाल यह है कि आखिर समस्या इतनी विकराल कैसे होती जा रही? इसका जवाब संसद में पेश हालिया रिपोर्ट में मिल जाता है। इसके मुताबिक इस वित्त वर्ष में प्रदूषण नियंत्रण योजना के लिए आवंटित 858 करोड़ रुपये में से मात्र 7.22 करोड़ रुपये यानी एक प्रतिशत से भी कम राशि खर्च की गई।

सरकारी तंत्र के ऐसे दुबलमूल रवैये की वजह से ही हवा के साथ साफ पानी के लिए भी हम तरस रहे हैं। हाल में आई दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी



इसकी खूबसूरती पर दाग लगाने के लिए भी वहीं कारण जिम्मेदार हैं, जो शहरों की हवा बिगाड़ रहे। सीमेंट, स्टील संयंत्रों से निकलने वाले धुएँ और इनका माल ढोने वाले हजारों ट्रकों की आवाजाही ने यहाँ की हवा को विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानकों से 22 गुना अधिक ज़हरीला बना दिया।

रिपोर्ट से साफ है कि प्रदूषण अब सिर्फ महानगरों की ही समस्या नहीं रह गया, बल्कि छोटे शहरों को भी ये अपनी चपेट में ले चुका है। इसकी गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगाइए कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में 13 भारत के हैं। दिल्ली एक बार फिर दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। इसके कुछ दिन बाद आई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट भी यही बता रही है कि बीती सदियों में दिल्ली सबसे प्रदूषित महानगरों में रही। 40 दिन तक तो हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में रही।

की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में बह रही यमुना नदी सीवेज बनकर रह गई है। इसमें फेकल कोलोफॉर्म (छूतम वेस्ट से पानी में आने वाला बैक्टीरिया) का स्तर तय मानक से 6400 गुना अधिक पाया गया। वहीं, जलीय जीवों के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन का स्तर भी तय मानक से 72 गुना कम हो चुका है। दिल्ली में अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट के लंबे समय तक यमुना में गिरने की वजह से इसकी यह हालत हो गई है।

यमुना की ऐसी हालत के पीछे एक और बड़ा कारण है और वह यह कि इस नदी को लेकर यहाँ सिर्फ राजनीति ही हुई, काम नहीं। नदी को साफ करने का वादा कर सत्ता में आई दिल्ली की नई सरकार की सीएम दावा कर रही हैं कि यमुना को भी अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तरह चमका देंगी। अब इस पर कितना यकीन करें क्योंकि ऐसे दावे तो पिछली सरकार ने भी किए थे।

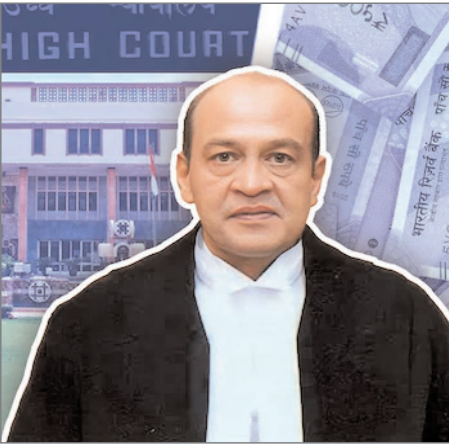
जज वर्मा मामले से जजों की नियुक्ति में केंद्र को मिला मौका

जज कैशकांड के बाद सुप्रीम कोर्ट की फजीहत दो कारणों से हो रही है। न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द करने और जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने से। आयोग को रद्द करने पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति धनखड़ द्वारा राजनीतिक दलों की बैठक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक आयोग को निरस्त करने के फैसले की तीखी भर्त्सना की गई। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाइकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले का विरोध किया है। एसोसिएशन ने हड़ताल के अलावा जस्टिस वर्मा की कोर्ट के बहिष्कार की चेतावनी दी है।

(योगेंद्र योगी)
स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक एक भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। अर्थात् किसी भी जज को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है। दरअसल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के बाद गंभीर किस्म के आरोपों के बाद किसी भी जज को हटाया जाना आसान नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर मिले लाखों रुपए के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया है। केंद्र सरकार ने संसद में कॉलेजियम व्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कानून पारित किया था। इस कानून के एक विवादस्पद प्रावधानों में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में भारत के प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम जजों और केन्द्रीय कानून मंत्री के अलावा दो जानी मानी हस्तियों को शामिल करने की व्यवस्था थी। वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून-एनजेसी को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। जस्टिस वर्मा नोट प्रकरण के बाद न्यायिक नियुक्ति आयोग फिर से लागू करने की सभावनता के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की उम्मीद फिर से पैदा हो गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में राजनीतिक दलों से कहा कि उन्हें जजों की तरफ से जजों की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक तंत्र के बारे में सोचना चाहिए। धनखड़ ने

कानून को रद्द करने के शीर्ष अदालत के फैसले को गलत बताया। उन्होंने वर्ष 2014 में सर्वसम्मति से बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को दूरदर्शी कदम बताया। इसका उद्देश्य एससी और एसटी के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के एकाधिकार को समाप्त करना था। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष



के नेता मल्लिकार्जुन खड्गे और टीएमसी के सुखेंद्रु शेखर रॉय सहित विपक्षी नेताओं ने सरकार से उन कदमों की रूपरेखा तैयार करने को कहा है जो वह उठाना चाहती है।

जज कैशकांड के बाद सुप्रीम कोर्ट की फजीहत दो कारणों से हो रही है। न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द करने और जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद

हाईकोर्ट में करने से। आयोग को रद्द करने पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति धनखड़ द्वारा राजनीतिक दलों की बैठक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक आयोग को निरस्त करने के फैसले की तीखी भर्त्सना की गई। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाइकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले का विरोध किया है। एसोसिएशन ने हड़ताल के अलावा जस्टिस वर्मा की कोर्ट के बहिष्कार की चेतावनी दी है। जस्टिस वर्मा प्रकरण के बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिर से उंगलियाँ उठने लगी हैं। न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं होने और इनमें परिवारवाद को वरीयता दिए जाने को अंकल जज सिंड्रोम कहते हैं।

जब जज बनाने के लिए अधिवक्ताओं के नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो किसी भी स्तर पर किसी से कोई राय नहीं ली जाती। ऐसे में जिन लोगों का नाम प्रस्तावित किया जाता है, उनमें से कई पूर्व न्यायाधीशों के परिवार से होते हैं या उनके संबंधी होते हैं। भारतीय विधि आयोग ने अपनी 230वीं रिपोर्ट में उच्च न्यायालयों में अंकल जजों की नियुक्ति के मामले का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि जिन जजों के परिजन किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं, उन्हें उसी उच्च न्यायालय में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। विवादों में घिरे जस्टिस वर्मा का अकेला मामला नहीं है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष परेशानी खड़ी हुई है। पूर्व में हाईकोर्ट के जजों खिलाफ इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव पिछले दिनों विश्व हिंदू

परिषद के कार्यक्रम में बयानबाजी को लेकर चर्चा में रही। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूरी जानकारी मांगी वहीं, संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग ने जोर पकड़ा। जस्टिस वी. रामास्वामी पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई थी। उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव 1993 में लोकसभा में लाया गया था। लेकिन यह प्रस्ताव गिर गया था क्योंकि उसे ज़रूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं हो सका। जस्टिस रामास्वामी 1990 में पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश थे तब उन पर आधिकारिक तौर पर अलॉट किए गए घर पर कब्जा किए जाने का आरोप लगा था।

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सोमित्र सेन देश के दूसरे जज थे जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा था। उनके खिलाफ 2011 में राज्य सभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। जस्टिस सोमित्र सेन ने महाभियोग चलाए जाने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को अपना इस्तीफा भेज दिया था। वह पहले ऐसे न्यायाधीश थे जिन पर उच्च सदन द्वारा कटाचार के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। वर्ष 2015 में राज्यसभा के 58 सदस्यों ने गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस जे.बी. पारदीवाला के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। जेबी पारदीवाला ने आरक्षण के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सांसदों ने अपने प्रस्ताव में अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ उनके अपशब्द कहे जाने पर आपत्ति जताई थी।



वोडा-आइडिया के शेयर पर सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, सेबी की हरी झंडी

नई दिल्ली, एंजेंसी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने सरकार को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) के शेयरधारकों के लिए खुली पेशकश लाने से छूट दे दी। यह छूट वीआईएल में स्पेक्ट्रम बकाया को इकट्ठी में बदलने के एवज में 3.4 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण के बाद दी गई है।



सरकार की 49 फीसदी हो जाएगी हिस्सेदारी- इस परिवर्तन से कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी वर्तमान के 22.6 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 49 प्रतिशत हो जाएगी - जिससे टेलीकॉम प्रोवाइडर वीआईएल अपने ग्राहक आधार को सेवा प्रदान करना जारी रख सकेगी और भारत में दूरसंचार पहुंच बढ़ा सकेगी। यह छूट देते हुए सेबी ने कहा कि फिलहाल भारत सरकार का वीआईएल के प्रबंधन या बोर्ड में भाग लेने का कोई इरादा नहीं है और दूरसंचार कंपनी के नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा, ऐसी होल्डिंग को सार्वजनिक शेयरधारिता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। पिछले महीने सरकार ने संकटग्रस्त कंपनी को एक जीवन देते हुए सितंबर, 2021 के दूरसंचार सुधार पैकेज के प्रावधानों के तहत वीआईएल के स्पेक्ट्रम नीलामी बकाया के 36,950 करोड़ रुपये को इकट्ठी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। सामान्य तौर पर भारत सरकार की शेयरधारिता को बढ़ाकर 48.99 प्रतिशत करने से अधिग्रहण नियमों के तहत खुली पेशकश की बाधघटा उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन नियामक ने सरकार को इससे छूट प्रदान की है।

तया है नियम

नियमों के तहत, किसी सूचीबद्ध कंपनी में 25 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी हासिल करने वाली संस्थाओं को शेयरधारकों के लिए एक खुली पेशकश करनी होती है। अपने आदेश में, नियामक ने उल्लेख किया कि वीआईएल द्वारा सरकार को एक बड़ी राशि का भुगतान किया जाना है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति पर संभावित बोझ डाल सकता है। इसके अलावा, भारत सरकार की ओर से एक खुली पेशकश की बाधघटा में नकदी की बड़ी मात्रा में निकासी शामिल है।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में से सरकार घटा रही है अपनी हिस्सेदारी

नई दिल्ली, एंजेंसी। सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में से सरकार ने अपनी हिस्सेदारी घटाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार की तरफ से फ्लोर प्राइस का ऐलान कर दिया गया है। सरकार ने बताया है कि कुल 4.83 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचा जाएगा। जिसके लिए कंपनी ने 2525 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से फ्लोर प्राइस तय किया है। 6 प्रतिशत गिरा कंपनी के शेयरों का भाव- निवेशकों को सरकार का यह फैसला पसंद नहीं आ रहा है। जिसकी वजह से कंपनी के शेयरों में आज शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर बीएसई में 2571.40 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 2558.75 रुपये (सुबह 9.45 बजे) पर आ गया। बता दें, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयरों का भाव 6 प्रतिशत टूट गया है। दीपम के सचिन अरुनिश चावला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 3 अप्रैल को किए गए पोस्ट में जानकारी दी, नॉन रिटेल निवेशकों के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का ऑफर फार सेल कर खुला जाएगा। वहीं, रिटेल निवेशक सोमवार को इस पर दांव लगा पाएंगे। सरकार की तरफ से 2.83 प्रतिशत हिस्सेदारी को घटाया जा रहा है।

2000 रुपये से कारोबार की शुरुआत

आज सालाना 35 लाख की कमाई



नई दिल्ली, एंजेंसी। किसी भी कारोबार में सफलता के लिए जरूरी है कि उसमें जानकारी होना। काफी एक्सपर्ट भी यही सलाह देते हैं कि बिना जानकारी के कारोबार शुरू करना नुकसान का सौदा हो सकता है। ऐसा ही कुछ किया सुंदरगढ़ (ओडिशा) के रहने वाले जतिंद बरवा ने। वह मशरूम का कारोबार करते हैं। इस कारोबार को शुरू करने से पहले उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली थी। आज वह लाखों रुपये सालाना कमा रहे हैं। जतिंद बरवा का कारोबार करने का शुरू से ही शौक था। जतिंद एमएससी करने के बाद इस उलझन में थे कि उन्हें सरकारी नौकरी करनी चाहिए या कारोबार की दुनिया में कदम रखना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने इन्फू से फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा किया। हालांकि जतिंद का खेती की ओर रूझान बड़े भाई को देखकर हुआ।

बड़े भाई से मिली प्रेरणा- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जतिंद बताते हैं कि उन्होंने अपने बड़े भाई को खेती में सफल होते देखा था। भाई को देख जतिंद ने भी खेती करने के बारे में सोचा। जतिंद का मानना है कि नौकरी में बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं। जबकि कारोबार काम की आजादी देता है। जतिंद ने अपने भाई से खेती की कुछ ट्रेनिंग ली। इसके बाद उन्होंने साल 2009 में 5 एकड़ जमीन लीज पर ली और सब्जियां उगाना शुरू कर दिया।

बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों ने डिपॉजिट रेट्स घटाने शुरू किए

एचडीएफसी, यस बैंक, बंधन और बजाज फाइनेंस ने घटा दिए हैं डिपॉजिट रेट्स

आरबीआई की एमपीसी इस हफ्ते की बैठक में रेपो रेट में और कटौती कर सकती है

नई दिल्ली, एंजेंसी। बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों ने डिपॉजिट रेट्स घटाने शुरू कर दिए हैं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरों में और कटौती कर सकता है साथ ही लिक्विडिटी (रुपये की उपलब्धता) में भी सुधार होने की बात कही जा रही है। एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक और एनबीएफसी बजाज फाइनेंस ने इस हफ्ते डिपॉजिट रेट्स घटा दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे आने वाले दिनों में लोन (उधार) पर ब्याज दरें भी कम होंगी और आरबीआई की नीतियों का असर आम लोगों तक जल्दी पहुंचेगा। आरबीआई ने जनवरी से सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे हैं। मंगलवार को उसने और 80,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदने का ऐलान किया। यानी आरबीआई बाजार में और पैसा डाल रही है ताकि ब्याज दरें कम हों।

इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, इस साल फरवरी में सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कमी की थी उम्मीद है कि एमपीसी की अगली मीटिंग में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती हो सकती है। अधिकतर बैंकों



से इस तिमाही में डिपॉजिट रेट्स कम करने की उम्मीद है। उन्होंने पहले ही रेपो रेट से जुड़े एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट के आधार पर डिपॉजिट रेट्स घटा दिए हैं लेकिन बैंकों का कहना है कि वो अभी अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स के आधार पर लोन की दरें तुरंत नहीं घटाएंगे।

डिपॉजिट रेट्स में कटौती से एमसीएलआर में कमी का रास्ता साफ होता है। एचडीएफसी बैंक, यस बैंक और बजाज फाइनेंस ने डिपॉजिट रेट्स 0.25-0.40 प्रतिशत तक घटा दिए हैं। बंधन बैंक ने सेविंग अकाउंट्स पर ब्याज दरों में आधी तक कटौती की है।

तया कहते हैं एक्सपर्ट

बैंक ऐसे वक्त में ब्याज दरें कम कर रहे हैं जब सरकार ने अप्रैल-जून के लिए अपनी सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की दरें जस की तस रखी हैं। इनमें आरबीआई बॉन्ड्स और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स पर ज्यादा से ज्यादा 8.2 प्रतिशत ब्याज मिलता है Money Honey फाइनेंश्ल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अनूप भैया कहते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट करने वालों को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। चार से पांच साल की लंबी अवधि के लिए ज्यादा ब्याज दरों पर पैसा लगा देना चाहिए। फाइनेंश्ल प्लानर्स बताते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट (सब्सिडिजिड पर्संद किए जाते हैं क्योंकि ये समझने में आसान होते हैं और नियमित रूप से पैसा मिलता रहता है। यह बाजार की स्थिति पर निर्भर नहीं होता। ये प्रोडक्ट्स रिटायर लोगों या उन निवेशकों को पर्संद आते हैं जो अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं और बिना किसी अनिश्चितता के काम को सरल रखना चाहते हैं। इसके मुकाबले, डेट फंड्स पर रिटर्न तय नहीं होता और चुने हुए फंड और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के आधार पर ये अस्थिर हो सकते हैं। ज्यादा ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के दौरान मार्केट टू मार्केट लाभ या नुकसान हो सकता है। ये कटौती खास तौर पर उन स्पेशल डिपॉजिटर्स पर केंद्रित है जो सीमित समय (31 मार्च तक) के लिए ज्यादा ब्याज दरों पर शुरू की गई थीं।

अंबानी ने खरीदे 6 करोड़ से ज्यादा शेयर, 265 रुपये तक जा सकता है भाव

नई दिल्ली, एंजेंसी। मुकेश अंबानी की कंपनी- जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अपने ज्वाइंट वेंचर को लेकर एक अहम ऐलान किया है। जियो फाइनेंशियल ने गुरुवार को कहा कि कंपनी और ब्लैकरोक ने अपने 50-50 ज्वाइंट वेंचर- जियो ब्लैकरोक इन्वेस्टमेंट एडवाइजंस प्राइवेट लिमिटेड के 6.65 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदे हैं। इसका फंस वैल्यू 10 प्रति शेयर है। इस लिहाज से कुल 66.5 करोड़ का निवेश हुआ है। बता दें कि यह ज्वाइंट वेंचर अपने व्यावसायिक संचालन को सपोर्ट देने के लिए इस फंड का उपयोग करेगा।



शेयर का हाल- बीएसई इंडेक्स पर गुरुवार को यह शेयर 230.45 रुपये पर था। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर 0.26 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। अप्रैल 2024 में शेयर की कीमत 394.70 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 198.60 रुपये है। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट- बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक विश्लेषकों ने सुझाव दिया है कि जियो फाइनेंशियल के शेयर ओवरसोलड लेवल से उबर चुके हैं और शॉर्ट टर्म में मजबूती देखी जा सकती है। आनंद राठी के वरिष्ठ प्रबंधक - तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जिगर एस पटेल ने बताया कि शेयर को समर्थन 220 रुपये और प्रतिरोध 236 रुपये पर मिलेगा। शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो 220 रुपये और 250 रुपये के बीच रहने का अनुमान है। स्टॉक्सबॉक्स के अमेय रानादिवे ने कहा कि पिछले दो हफ्तों में जियो फाइनेंशियल में तेजी का रुख रहा है, जो ओवरसोलड स्तरों से उबर रहा है। यह शेयर अल्पावधि में मजबूती का संकेत दे रहा है। शेयर का संभावित लक्ष्य 257-265 रुपये की सीमा में रह सकता है।

दिसंबर तिमाही के नतीजे

दिसंबर 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही में जियो फाइनेंशियल का 295 करोड़ रुपये पर स्थिर रहा। जियो फाइनेंशियल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 294 करोड़ रुपये का मुनाफा अर्जित किया था। तिमाही में कुल आय बढ़कर 449 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 414 करोड़ थी। कुल खर्च में भी सालाना आधार पर वृद्धि देखी गई। यह बढ़कर 131 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले इसी तिमाही में 99 करोड़ रुपये था।

1 शेयर पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी

नई दिल्ली, एंजेंसी। पेनी स्टॉक केबीसी ग्लोबल लिमिटेड के शेयर आज स्टॉक मार्केट में एक्स-बोनस के तौर पर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया गया है। बता दें, केबीसी ग्लोबल लिमिटेड के शेयरों का भाव 1 रुपये से भी कम का है। हर शेयर पर एक शेयर का फायदा- एक्सचेंज को दी जानकारी में केबीसी ग्लोबल लिमिटेड ने बताया था कि 1 रुपये के फंस वैल्यू वाले एक शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया गया है। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने पहले से ही 4 अप्रैल की तारीख को रिफॉर्ड डेट तय किया था। जो कि आज है। 2021 में बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी- इस पेनी स्टॉक ने 2021 में भी बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 4 शेयर बोनस शेयर तौर पर दिए थे। वहीं, केबीसी ग्लोबल लिमिटेड के शेयरों का बंटवारा 2 बार हुआ है। पहली बार कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2020 में हुआ था। तब कंपनी ने अपने शेयरों को 5 हिस्सों में बांट दिया था। उसके बाद कंपनी के शेयरों को 2021 में बांट दिया गया था। तब कंपनी ने अपने शेयरों का बंटवारा 2 हिस्सों में किया था। इस दूसरी बार स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फंस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।

● कंपनी के शेयरों में लगा अपर सर्किट- बीएसई में आज यह स्टॉक 3.85 प्रतिशत की उछाल के बाद 0.54 रुपये के लेवल पर खुला है। बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी के शेयरों का यह अपर सर्किट है। बता दें, आज इस स्टॉक को खरीदने वाले निवेशकों को बोनस शेयर का लाभ नहीं मिलेगा।

टाटा मोटर्स के शेयर डाउनग्रेड, टार्गेट प्राइस भी घटाया, अब बेचने की लगी होड़



नई दिल्ली, एंजेंसी। पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड को ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने अपनी हाई कन्विकशन आउटपरफॉर्म लिस्ट से हटा दिया है। सीएलएसए ने टाटा मोटर्स को फिर से आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है और इसके शेयर का टार्गेट प्राइस 18 प्रतिशत घटाकर 930 से 765 कर दिया है। नया टार्गेट गुरुवार के क्लोजिंग प्राइस से 17 प्रतिशत की संभावित बढ़त दिखाता है। आज यह स्टॉक करीब 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 625 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है।

34 एनॉलिसिस में से 21 ने कहा-खरीदो- टाटा मोटर्स पर नजर रखने वाले 34 एनॉलिसिस में से 21 ने 8 ने होल्ड और 5 ने स्ट्रडग रेटिंग दी है। टाटा मोटर्स के शेयर अब अपने 52-हफ्ते के निचले स्तर 606.30 रुपये की ओर बढ़ रहा है।

ट्रैप के टैरिफ का असर

टाटा मोटर्स को इस लिस्ट में शामिल किए जाने के महज दो महीने के अंदर ही हटा दिया गया है। सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका में 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगने और जगुआर मॉडल्स की उत्पादन बंदी के कारण जगुआर लैंड रोवर की वित्तीय वर्ष 2026 में 14 प्रतिशत गिर सकती है। इससे टाटा मोटर्स का इबीआईटी मार्जिन वित्तीय वर्ष 2026-27 में 9 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत रह जाएगा।

इस वजह से सीएलएसए ने जगुआर लैंड रोवर के इबीआईटीटी अनुमान को कम किया है, हालांकि उसे उम्मीद है कि जगुआर लैंड रोवर वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 दोनों में फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव रहेगा।

जगुआर लैंड रोवर को ग्रोथ की चुनौतियां

कम अर्वाधि में जगुआर लैंड रोवर को ग्रोथ की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सीएलएसए ने जगुआर लैंड रोवर का मल्टीपल 2.5x से घटाकर 2x कर दिया है।

भारत में कमर्शियल व्हीकल्स का साइकिल वित्तीय वर्ष 2026 में निचले स्तर पर पहुंच सकता है। इसलिए, सीएलएसए ने टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस का वैल्यूएशन वित्तीय वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया है, जिससे 127 प्रति शेयर की बढ़त हो सकती है। सीएलएसए ने कहा कि यह जगुआर लैंड रोवर पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर देगा।

बिजनेस अपडेट के बाद डीमार्ट के शेयर लुढ़के, 4,000 के नीचे आया भाव

नई दिल्ली, एंजेंसी। रिटेल चेन डीमार्ट को ऑपरेट करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्केट्स के शेयर 5 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,000 के नीचे आकर 3,946 प्रति शेयर पर पहुंच गए। यह गिरावट कंपनी के मार्च 2025 तिमाही के बिजनेस अपडेट के बाद आई, जो विश्लेषकों की उम्मीदों से कम रहा।

पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा स्टोर खोले- गुरुवार को एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने मार्च तिमाही में स्टैंडअलोन ऑपरेटिंग रेवेन्यू 14,462 करोड़ बताया, जो पिछले साल की समान तिमाही के 12,393 करोड़ से 16.67 प्रतिशत अधिक है। इस तिमाही में कंपनी ने 28 नए स्टोर खोले, जो पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा है। अब कुल स्टोर संख्या 415 हो गई है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने कुल 50 नए स्टोर जोड़े, जो वित्त वर्ष 24 (41 स्टोर) और वित्त वर्ष 23 (40 स्टोर) से अधिक है। यह संख्या विश्लेषकों के अनुमान (40 स्टोर) से भी बेहतर रही। कंपनी ने पहले ही अपने इन्वेस्टर्स डे में



लॉग टर्म में स्टोर वृद्धि दर 10-15 प्रतिशत बनाए रखने का लक्ष्य रखा था।

उम्मीदों से कमजोर रहे नतीजे- हालांकि, दिसंबर तिमाही में कंपनी के नतीजे उम्मीदों से कमजोर रहे, क्योंकि मेट्रो शहरों में क्रिक कॉमर्स (तेज ऑनलाइन, डिलीवरी) की वजह से स्टोर परफॉर्मंस प्रभावित हुई-हालांकि क्यू2एफवाय25 के मुकाबले असर कम था। एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपनी रक रिपोर्ट में कहा

था कि डीमार्ट को आने वाले समय में स्टोर मेट्रिक्स सुधारने में चुनौतियां रहेंगी। इसकी 4 वजहें हैं।

प्राइसिंग प्रेशर से ग्रोथ और मार्जिन पर दबाव - विश्लेषकों का मानना है कि क्रिक कॉमर्स कंपनियों (जैसे जेटो, बिलिकिट) द्वारा हाल में जुटाए गए फंड्स ने प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। हालांकि डीमार्ट का वैल्यू-बेस्ड मॉडल लंबे समय में क्रिक कॉमर्स के साथ चल सकता है।



आईपीएल में इस दशक में सबसे ज्यादा शतक जोस बटलर के नाम

आईपीएल 2025: इस नंबर पर हैं गिल, राहुल और कोहली

नई दिल्ली, एजेंसी। आईपीएल 2025 का कारवां आगे बढ़ रहा है और एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले क्रिकेट फैंस को देखने को मिल रहे हैं। जैसे इस सीजन में 14 मैच खत्म होने तक सिर्फ एक शतक लगा है जो केकेआर के बल्लेबाज इशान किशन ने लगाया है। जैसे इस सीजन में और भी शतक देखने को मिलेंगे, लेकिन इस दशक में यानी साल 2020 से अब तक आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर की बात की जाए तो इसमें पहले नंबर पर जोस बटलर हैं। जोस बटलर इस सीजन में आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने अपनी टीम के लिए सीजन के तीसरे मैच में आरसीबी खिलाफ नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली थी और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। जोस बटलर आईपीएल के कुछ बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं और वो विकेटकीपिंग भी करते हैं। बटलर का आईपीएल में रिकॉर्ड भी

काफी अच्छा रहा है। आईपीएल में जैसे तो सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली (8 शतक) के नाम पर दर्ज है और उसके बाद दूसरे नंबर पर जोस बटलर हैं जिन्होंने अब तक 7 शतक लगाए हैं, लेकिन इस दशक में यानी साल 2020 से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर की लिस्ट में बटलर पहले नंबर पर हैं। बटलर ने आईपीएल में अपने सारे शतक इस दशक में यानी साल 2020 से लगाए हैं।

इस दशक में बटलर ने अब तक आईपीएल की 64 पारियों में सबसे ज्यादा 7 शतक लगाए हैं जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर शुभमन गिल हैं जिन्होंने 79 पारियों में 4 शतक ठोकें हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से केएल राहुल और विराट कोहली मौजूद हैं। कोहली ने इस दशक में आईपीएल में 78 पारियों में 3 शतक जबकि केएल राहुल ने 66 पारियों में कुल 3 शतक जड़े हैं।



दशक में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले

7 - जोस बटलर (64 पारी)

4 - शुभमन गिल (79 पारी)

3 - केएल राहुल (66 पारी)

3 - विराट कोहली (78 पारी)

200 विकेट लेकर सुनील नरेन ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज

नई दिल्ली, एजेंसी। गुरुवार रात आईपीएल में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रनों से हराया। मुकाबले में एक विकेट लेकर केकेआर गेंदबाज सुनील नरेन ने इतिहास रचा, उन्होंने इस फ्रेंचाइजी के लिए 200 विकेट पूरे कर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। वह दुनिया के दूसरे ही गेंदबाज हैं, जिन्होंने लीग क्रिकेट में किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए 200 विकेट लिए हैं। 201 रनों का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 120 रनों पर ढेर हो गई। वैभव अरोड़ा ने देविंस हेड (4), इशान किशन (2) के रूप में 2 विकेट जल्दी गिरा दिए। अभिषेक शर्मा भी 2 रन बनाकर हर्षित राणा का शिकार बने। टीम ने टॉप 3 बल्लेबाजों के विकेट सिर्फ 9 रन पर गंवा दिए थे। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जानी जाने वाली टीम का गुरुवार को केकेआर ने बुरा हाल किया। इस मैच में स्पिनर सुनील नरेन ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। सुनील नरेन ने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर इस



मैच में अपना एकमात्र विकेट कामिन्दु मेंडिस के रूप में लिया। मेंडिस ने 20 गेंदों में 27 रन बनाए, इस विकेट के साथ सुनील नरेन ने केकेआर फ्रेंचाइजी के लिए 200 विकेट पूरे कर लिए हैं। सुनील नरेन ने आईपीएल में केकेआर के लिए 182 पूरे किए हैं, उनके नाम इसी फ्रेंचाइजी के लिए चैंपियंस लीग टी20 में 18 विकेट हैं। सुनील नरेन वर्ल्ड क्रिकेट में दूसरे ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने किसी एक फ्रेंचाइजी टीम के लिए 200 विकेट लिए हैं। उनसे पहले से पटेल ने ऐसा किया है। नॉटिचमशायर टीम के लिए उन्होंने 208 विकेट लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स इस शानदार जीत के बाद अंक तालिका में 5वें नंबर पर आ गई है जबकि इससे पहले वो सबसे नीचे (10वें) थी।



इन 5 स्लॉग ओवर्स में लगा दी लंका, जब-जब खेले तब-तब बजाया बंड

हैदराबाद के जानी दुश्मन है अर्यर

नई दिल्ली, एजेंसी। सनराइजर्स हैदराबाद को खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 3 अप्रैल को हुए मुकाबले में 15 ओवर का खेल हो चुका था। चयनकर्ता केकेआर अर्यर 10 गेंदों पर 11 तो रिकू सिंह 8 गेंदों पर 6 रन बनाकर खेल रहे थे। कोलकाता की टीम का स्कोर हुआ था 122/4.

इस स्कोर के बाद ही केकेआर अर्यर और रिकू सिंह ने ऐसा मोर्चा संभाला कि कोलकाता ने 20 ओवर्स में पूरे 200 रन बना डाले। इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच भले ही चयनकर्ता के वैभव अरोड़ा रहे, पर कोलकाता के लिए मैच बनाने का काम प्रमुख तौर पर केकेआर अर्यर ने किया। वरना एक समय कोलकाता के लिए 200 का स्कोर दूर के

का 16वां ओवर एसआरएच के पेसर मोहम्मद शमी करने आए, इस ओवर में अर्यर और रिकू ने मिलकर 12 रन बनाए, फिर 17वें ओवर हर्षल पटेल के हाथ में था, यहाँ 15 रन आए, 18वें ओवर में समिरतजीत सिंह अर्यर और रिकू के सामने पड़े तो फिर 17 रन आए, जब सभी गेंदबाज स्लॉग ओवर में पिट रहे थे तो 19 ओवर खुद कप्तान कमिंस लेकर आए, लेकिन कमिंस की रिकू और अर्यर ने ऐसी खातिरदारी की उनके ओवर में 21 रन कूट दिए, 20वां ओवर हर्षल पटेल ने फेंका, जहाँ कुल 13 रन आए, इस ओवर में तीसरी गेंद पर 29 गेंदों पर 60 रन की पारी खेलने के बाद केकेआर अर्यर आउट तो हो गए, लेकिन वो तब तक अपना काम कर चुके थे, अर्यर से पहले अंगकृष रसुवशी ने 32 रनों पर 50 रनों की पारी खेली, वहीं कोलकाता की ओर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 38 तो रिकू सिंह (32 नाबाद) ने भी सधी पारियां खेलीं। इस वजह से कोलकाता ने निर्धारित 20 ओवर्स में 200/6 का स्कोर बनाया, बाद में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम वैभव अरोड़ा के नेतृत्व में इस तरह सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पर टूटी कि उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला, को मुकाबले में 80 रनों से हार मिली, जो उसकी रनों के लिहाज से आईपीएल में सबसे बड़ी हार रही, वहीं एसआरएच की इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार रही, वो केवल अपना पहला मुकाबला ही जीत सकी थीं।

हितेश ने रचा इतिहास, जदुमनी, सचिन और विशाल को बॉन्ज से करना पड़ा संतोष



नई दिल्ली, एजेंसी। ब्राजील में हो रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के फाइनल में पहुंचकर भारत के बॉक्सर हितेश ने शुक्रवार (4 अप्रैल) को इतिहास रच दिया। वह वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का खिताबी मुकाबला खेलने वाले पहले भारतीय होंगे। उनके अलावा भारत के 3 अन्य मुक्केबाज जदुमनी सिंह, सचिन और विशाल को सेमीफाइनल में हार मिली। तीनों को बॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। हितेश ने 70 किलोग्राम कैटेगरी फ्रांस के मकान त्राओरे को 5-0 से हराया। इससे पहले हितेश ने इटली के गैब्रिएल गुड्डी रोन्टानी को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। सेमीफाइनल के अन्य मुकाबलों की बात करें तो 60 किलोग्राम कैटेगरी में जदुमनी सिंह को उजबेकिस्तान के ए.जलिलोव ने 2-3 से हराया। वह ब्रिटेन के एलिस ट्रोब्रिज को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे थे। शुरुआती दौर में बाई मिलने के कारण सचिन (60 किग्रा) और विशाल (90 किग्रा) सीधे सेमीफाइनल में उतरे। सचिन को पोलैंड के पवेल ब्राच से हार का सामना करना पड़ा। विशाल को उजबेकिस्तान के टी. खबीबुल्लाएव ने 0-5 से हराया।

आईपीएल 2025

पंजाब और राजस्थान के मुकाबले में जायसवाल की फॉर्म पर रहेगी नजर



मुल्लापुर, एजेंसी। राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने नियमित कप्तान संजू सैमसन की अगुवाई में पंजाब किंग्स के खिलाफ शनिवार को यहां जब इंडियन प्रीमियर लीग का मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी तो सभी की निगाह खराब फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल पर टिकी रहेगी जो मैदान के बाहर की घटनाओं के बजाय अपने प्रदर्शन से सुखियां बटोरना चाहेंगे। जायसवाल हाल में तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने मुंबई की टीम के अपने एक सीनियर साथी के साथ कथित मतभेदों के कारण घरेलू क्रिकेट में गोवा की तरफ से खेलने का फैसला किया। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज आईपीएल में अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। उन्होंने दिन मैच में केवल 34 रन बनाए हैं जिसका उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। जायसवाल की खराब फॉर्म का एक कारण उनका मैच अभ्यास की कमी है क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी में वनडे क्रिकेट में पदार्पण के बाद वह आईपीएल से पहले किसी प्रतिस्पर्धी मैच में नहीं खेले थे। उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी की टीम से भी बाहर कर दिया गया था। सैमसन की उंगली में चोट के कारण राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को पहले तीन मैच के लिए कप्तान नियुक्त किया था और यह स्पष्ट नहीं है कि जायसवाल को यह फैसला नागवार गुजरा या नहीं। लेकिन यह बात किसी से छुपी नहीं है कि जायसवाल आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं लेकिन अभी उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करना होगा क्योंकि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में फॉर्म बद से बदतर होने में देर नहीं लगती। रियान पराग की कप्तानी में नेतृत्व कौशल की अनुभवहीनता स्पष्ट नजर आई लेकिन इस बीच उसकी टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया जिससे उसके खिलाड़ी आत्मविश्वास हासिल करना चाहेंगे। रॉयल्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे जिन्होंने लगातार दो अर्धशतक जमा कर अपनी शानदार फॉर्म का परिचय दिया है। वह लंबे शॉट खेलने से नहीं हिचकिचा रहे हैं। इसका सबूत यह है कि उन्होंने अभी तक केवल दो मैच में 13 छक्के लगाए हैं।

आईपीएल के लिए हनीमून किया कैसिल, बलिदान नहीं गया बेकार, एसआरएच के लिए डेब्यू में उगली आग



नई दिल्ली, एजेंसी। श्रीलंका के प्रतिभावान खिलाड़ी कामिन्दु मेंडिस ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए अपना आईपीएल डेब्यू किया, उन्होंने अपने डेब्यू मैच में एक विकेट भी लिया। तारीख 3 अप्रैल, गुरुवार का दिन जब कामिन्दु मेंडिस ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए अपना आईपीएल डेब्यू किया। श्रीलंका का यह प्रतिभाशाली गेंदबाज दोनों हाथों से बॉलिंग करता है, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, उनके बैट से 27 रनों की पारी निकली और उन्होंने अपने डेब्यू मैच में एक विकेट भी लिया। मगर मेंडिस एक अन्य कारण से भी चर्चा में आ गए हैं क्योंकि अपने आईपीएल डेब्यू की वजह से उन्होंने अपने हनीमून तक का त्याग कर दिया, अभी कुछ दिन पहले ही मार्च 2025 में कामिन्दु मेंडिस ने अपनी लॉन्ग-टैम गल्लफेंड निशानी से शादी रचाई है, दोनों का रिश्ता लंबे समय से चर्चा में रहा है और उन्होंने पिछले साल अप्रैल में सगाई कर ली थी, जब शादी हुई तब मेंडिस ने एक कार्ड पर खुबसूरत संदेश लिख कर बताया था कि वो अपनी सोलमेट से शादी कर रहे हैं और निशानी से बहुत प्यार करते हैं, खेर शादी के कुछ समय बाद अब विख्यात वेडिंग प्लानर पशुम गुनावर्दना ने मेंडिस के हनीमून के कैसिल होने की जानकारी दी है, पशुम गुनावर्दना ने कामिन्दु मेंडिस के हनीमून प्लान की जानकारी देकर बताया कि कामिन्दु मेंडिस और निशानी श्रीलंका में ही हापुताले नाम की जगह पर हनीमून मनाने गए थे, उन्होंने विदेश का ट्रिप इसलिए प्लान नहीं किया क्योंकि कामिन्दु मेंडिस को आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेब्यू करना था, हनीमून के बजाय आईपीएल को तवज्जो देना दिखाता है कि इस श्रीलंकाई खिलाड़ी को क्रिकेट से कितना प्यार है।

क्या बढ़ेगी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि, शीर्ष खिलाड़ियों ने की मांग

वॉशिंगटन, एजेंसी। अभी ऑस्ट्रेलियाई ओपन और फ्रेंच ओपन की कुल पुरस्कार राशि करीब 58 मिलियन डॉलर है, जबकि विंबलडन की करीब 64 मिलियन डॉलर और अमेरिकी ओपन की लगभग 75 मिलियन डॉलर है। नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, अरिना सवालेंका और कोको गॉफ जैसे 20 प्रमुख टेनिस खिलाड़ियों ने चारो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि बढ़ाने की मांग की है। इतना ही नहीं, इन दिग्गज और स्टार टेनिस खिलाड़ियों ने उन्हें प्रभावित करने वाले फैसलों में उनकी बात को अधिक तवज्जो देने की मांग की है। इन स्टार्स ने इस संबंध में चारो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के प्रमुखों को पत्र लिखा है। यह पत्र 21 मार्च को लिखा गया था।

ऑस्ट्रेलियाई ओपन के प्रमुख क्रैग टिली हैं, जबकि फ्रेंच ओपन के प्रमुख स्टीफन मोरेल, विंबलडन के प्रमुख सैली बोलेटन और अमेरिकी ओपन के प्रमुख ल्यू

शेर हैं। इन सभी को संबोधित करते हुए खिलाड़ियों ने पत्र में इस महीने होने वाले मैट्रिड ओपन के दौरान अपने प्रतिनिधियों और चारों ग्रैंड स्लैम के प्रमुखों के बीच बैठक करने का भी अनुरोध किया है।

इस पत्र में पुरुष रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर हैं, जबकि महिला वर्ग में शीर्ष-11 खिलाड़ियों में से केवल एलिना रयबाकिना के इस पर हस्ताक्षर नहीं हैं। अभी ऑस्ट्रेलियाई ओपन और फ्रेंच ओपन की कुल पुरस्कार राशि करीब 58 मिलियन डॉलर (करीब 494 करोड़ रुपये) है, जबकि विंबलडन की करीब 64 मिलियन डॉलर (करीब 545 करोड़ रुपये) और अमेरिकी ओपन की लगभग 75 मिलियन डॉलर (करीब 639 करोड़ रुपये) है। इस राशि में से विजेताओं-उपविजेताओं समेत अन्य हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि बांटी जाती है।

अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने घोषणा की है कि इस

साल का होपमैन कप इटली के दक्षिणी शहर बारी में खेला जाएगा। इस मिश्रित टीम टूर्नामेंट में इटली, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और मौजूदा चैंपियन क्रोएशिया की टीमों हिस्सा लेंगी। इसका आयोजन विंबलडन के एक सप्ताह बाद 16 से 20 जुलाई तक किया जाएगा। होपमैन कप के लिए टीमों में एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी शामिल होते हैं। इसके एक मुकाबले में एक पुरुष एकल मैच, एक महिला एकल मैच और एक मिश्रित युगल मैच शामिल होता है। इस टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को रैंकिंग अंक नहीं मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी हैरी होपमैन के नाम पर, होपमैन कप 1989 में शुरू हुआ और 2020 तक हर साल खेला जाता था। पहले 30 वर्ष तक इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में टेनिस सत्र के पहले सप्ताह में किया जाता था। आखिरी बार इसका आयोजन 2023 में फ्रांस में हुआ था जिसमें क्रोएशिया के डोना वेकिच और बोर्ना कोरिच चैंपियन बने थे।



संक्षिप्त समाचार

वक्फ विधेयक को “बहुत जल्द” उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी कांग्रेस



नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वह संसद में पारित 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025' की संवैधानिकता को “बहुत जल्द” उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025' को बहुसंख्यक को मंजूरी दे दी। इसी के साथ संसद में यह विधेयक पारित हो गया। लोकसभा ने बुधवार देर रात करीब दो बजे इस विधेयक को पारित कर दिया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, “ कांग्रेस वक्फ (संशोधन) विधेयक की संवैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में बहुत जल्द चुनौती देगी।” उन्होंने कहा, “...हम भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और परंपराओं पर मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध करते रहेंगे।” रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीए) 2019' को चुनौती दी जिस पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जारी है। उन्होंने कहा कि 'आरटीआई (सूचना का अधिकार) अधिनियम, 2005' में 2019 के संशोधनों को भी कांग्रेस ने चुनौती दी जिस पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जारी है। कांग्रेस नेता ने कहा, “ 'निर्वाचन का संचालन नियम (2024)' में संशोधनों की वैधता को कांग्रेस ने चुनौती दी और उसकी उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो रही है।” कांग्रेस नेता ने कहा, “ 'उपासना स्थल अधिनियम, 1991' की मूल भावना को बनाए रखने संबंधी कांग्रेस की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की जा रही है।

विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी भाजपा, अमित शाह करेंगे बिहार, बंगाल और तमिलनाडु का दौरा

नई दिल्ली, एजेंसी। गृह मंत्री अमित शाह आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस महीने बिहार, परिचम बंगाल, तमिलनाडु की यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के बाद भी वे कई बार वहां जाएंगे, क्योंकि भाजपा बिहार में अपने सहयोगियों के साथ सत्ता बरकरार रखना चाहती है और दो अन्य राज्यों में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहती है। सूत्रों ने बताया कि शाह इन राज्यों में चुनाव तक लगभग हर महीने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की संगठनात्मक बैठकों आयोजित करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके 14 और 15 अप्रैल को परिचम बंगाल में तथा 30 अप्रैल को बिहार में रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

डीएनए रिपोर्ट पिता तय कर सकती है, सहमति का अभाव नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को किया बरी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में एक अहम फैसला देते हुए 10 साल जेल की सजा पाने वाले दोषी को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से केवल पितृत्व साबित होता है, सहमति का अभाव साबित नहीं होता।

जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट से भले ही यह साबित हो गया कि महिला की कोख से जन्मे बच्चे का जैविक पिता आरोपी ही है, लेकिन अकेले गर्भावस्था दुष्कर्म का अपराध सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है, जब तक कि यह भी न साबित किया जाए कि संबंध सहमति के बिना बनाया गया था।

हाईकोर्ट ने 20 मार्च को सुनाए गए अपने फैसले में कहा, डीएनए रिपोर्ट केवल पितृत्व को साबित करती है- यह सहमति के अभाव को न तो सिद्ध नहीं करती है और न ही कर सकती है। यह एक स्थापित कानून है कि आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत अपराध की सिद्धि सहमति के अभाव पर निर्भर करती है। फैसले में कहा गया कि



घटना से जुड़ी परिस्थितियों ने अभियोजन पक्ष के मामले को 'अत्यधिक असंभव' बना दिया है। जस्टिस महाजन ने फैसले में इस संभावना से भी इनकार नहीं किया कि बिना किसी स्पष्टीकरण के देरी से दर्ज कराई गई एफआईआर 'सामाजिक दबाव का नतीजा' हो सकती है।

उन्होंने कहा, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोप सहमति से बने संबंध को बलात्कार के रूप में स्थापित करने के लिए लगाए गए थे, ताकि आरोप लगाने वाली महिला और उसके परिवार को समाज के तानों का

सामना न करना पड़े। जस्टिस महाजन ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, कानून बेशक केवल चुप्पी को सहमति नहीं मानता, लेकिन यह उचित संदेह से परे सबूतों के अभाव में दोषी भी नहीं ठहरता। इस मामले में संदेह बना हुआ है - अटकलों के कारण नहीं, बल्कि सबूत के अभाव के कारण। हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमे के दौरान न सिर्फ महिला के बयानों में विरोधाभास पाया गया, बल्कि दुष्कर्म की पुष्टि करने के लिए मैडिकल और फॉरेंसिक सबूत भी नहीं मिले।

दिल्ली में जल्द पेपर और फेसलेस की मिलेगी सुविधा

रेखा गुप्ता सरकार बना रही प्लान; आपको क्या होगा फायदा

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार अगले कुछ महीनों में संपत्तियों की सेल डीड के रजिस्ट्रेशन को पेपर और फेसलेस बना सकती है। नए सिस्टम में अधिकारियों और नागरिकों दोनों के लिए सभी निषिद्ध संपत्तियों की सूची भी उपलब्ध होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन्हें धोखाधड़ी से बचा न जाए और इनके सेल डीड पंजीकरण को रोका जा सके।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) आशीष चंद्र वर्मा ने गुरुवार को सभी स्ट्रेकहोल्डर्स के साथ बैठक की, जिसमें शहर के नागरिकों के लिए संपत्तियों की सेल डीड के पंजीकरण को सुविधाजनक और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग ने प्रक्रियाओं को मजबूत करने और सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए संभावित समाधान सुझाने के लिए डेलीटैड को सलाहकार के तौर पर शामिल किया है। पोर्टल में नागरिकों के लिए एक डॉप-डाउन मॉड्यूल भी होगा, जिससे वे निषिद्ध संपत्तियों - विवादित, शत्रु, ग्राम

सभा भूमि और वक्फ के अलावा अवैध निर्माण के लिए नागरिक एजेंसियों द्वारा बुक की गई संपत्तियों को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, वर्मा ने कहा, हम चाहते हैं कि सिस्टम पूरी तरह से फेसलेस हो और इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप न हो। इसके लिए हमें तकनीकी बदलाव और कियोस्क स्थापित करने होंगे। जहां लोग जाकर पंजीकरण करा सकें और दस्तावेज अपलोड कर सकें। वर्मा ने कहा कि यह परियोजना नई सरकार की प्राथमिकता है और इसे इसी साल पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली ने सब-रजिस्ट्रारों द्वारा सेल डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत और 25 अन्य ऐसे दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) का उपयोग करना शुरू कर दिया है। सेल डीड पंजीकरण पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को एमसीडी के मूल्यांकन और संग्रह विभाग की डॉप-डाउन मॉड्यूल भी होगा, जिससे वे निषिद्ध संपत्तियों - विवादित, शत्रु, ग्राम

मायावती ने वक्फ विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने की आलोचना की

नई दिल्ली, एजेंसी। बसपा नेता ने विधेयक पारित करने में सरकार की 'जल्दबाजी' पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने जल्दबाजी में इस विधेयक को पेश किया और पारित करवाया, जो उचित नहीं है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि इस विधेयक को जनता की चिंताओं एवं शंकाओं को दूर करने के बाद ही पेश किया जाना चाहिए था। उनकी यह टिप्पणी बहुसंख्यक देर रात को राज्यसभा द्वारा विधेयक को पारित करने के बाद आई। विधेयक को लोकसभा में मंजूरी मिल चुकी है, जहां विषय ने इसका कड़ा विरोध किया था। मायावती ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर सत्ता व विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार अगर जनता को इस विधेयक को समझने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी संदेहों को भी दूर करके इस विधेयक को लाती, तो बेहतर होता।

दिल्ली के शाहीनबाग में उड़ाए जा रहे ड्रोन, जामिया नगर से जामा मस्जिद तक पुलिस ही पुलिस

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधित विधेयक पास होने के बाद दिल्ली में पुलिस अलर्ट पर है। विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के शाहीनबाग में जहां ड्रोन से निगरानी की जा रही है तो जामिया नगर से जामा मस्जिद तक मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। बिल पास होने के बाद पहला जुमा होने की वजह से मस्जिदों के आसपास भी निगरानी बढ़ी देखी। दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड ऐक्शन फोर्स ने भी अलग-अलग इलाकों में फ्लैग मार्च किया। गलियों और बाजारों से एक साथ सैकड़ों सुरक्षाकर्मी यह संदेश देते हुए निकले कि गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करने वालों पर सख्त ऐक्शन लिया जाएगा। जामिया नगर, जामा मस्जिद, मुस्तफाबाद, जहांगीरपुरी समेत कई इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नजर आए। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी अलर्ट मोड पर हैं। कंट्रोल रूम से हर इलाके की निगरानी की जा रही है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बाहर किसी तरह के प्रदर्शन या उपद्रव की स्थिति से निपटने के लिए सीआरपीएफ की टुकड़ियों को तैनात किया गया। विश्वविद्यालय के गेट संख्या 7 के पास काफी संख्या में सीआरपीएफकर्मी तैनात दिखाई दिए। इसके अलावा पुलिस वैन इत्यादि के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी तैनात दिखे। यहां किसी भी तरह के प्रदर्शन, विरोध या असामान्य तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली।



उपद्रव से निपटने के इंतजाम किए गए। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में खामोशी छाई रही। वहीं, कुछ स्थानों पर अलग-अलग संगठनों ने मिठाई बांटेकर खुशी भी जताई। इस बीच, संवेदनशील इलाकों में सुबह से सुरक्षाबल मुस्तैद नजर आए। सुरक्षाबलों ने शाम को फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का अहसास कराया। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी गई। अस्पृह्वीन ओबेसी की पार्टी एआईएमआईएम ने वक्फ बिल के विरोध में दिल्ली से आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान किया है। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने शाहीनबाग की ओर इशारा करते हुए कहा था कि आंदोलन की शुरुआत वहीं से होगी जहां खत्म हुई थी। बता दें कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीनबाग में महिलाएं लंबे समय तक धरने पर बैठी रही थीं।

भाजपा के आते ही 82 तक बढ़ गई स्कूलों की फीस, बच्चों को परेशान कर रहे

नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर बिजली कटौती के बाद अब एक और बड़ा आरोप लगा दिया है। मामला स्कूलों की फीस से जुड़ा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज का दावा है कि भाजपा के आते ही स्कूलों की फीस भी बढ़नी शुरू हो गई है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार ने बिजली कटौती के बाद अब मिडिल क्लास पर दूसरा बड़ा प्रहार किया है। एक अप्रैल से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई है।



उन्होंने कहा कि ये तकरीबन हर स्कूल में हुआ है। कहीं पर 20 तो कहीं पर 40-65 फीसदी स्कूल की फीस बढ़ा दी गई है। उनका दावा है कि कहीं तो यह आंकड़ा 82 फीसदी तक भी पहुंच गया है। उन्होंने कहा, एक अखबार के मुताबिक एक नामी स्कूल की ड्राकरा, वसंत कुंज और रोहिणी ब्रांच में फीस बढ़ाने के बाद बच्चों को परेशान किया जा रहा है।

सालवन पब्लिक स्कूल ने कहा है कि ये 82 फीसदी फीस बढ़ाएगा। 57 फीसदी बढ़ा दी है और 25 फीसदी और बढ़ाएगा। जिन्होंने बढ़ी हुई फीस नहीं दी है, उनके रिजल्ट रोक लिए गए हैं। माता-पिता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह उन्हें अन्य कई स्कूलों के उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, केजरीवा सरकार के दौरान अगर फीस बढ़ती तो पहले विधायक स्कूल के बाहर पहुंच जाता था लेकिन बीजेपी के विधायक बच्चों के परेशान कर साथ खड़े नहीं दिखे। सौरभ भारद्वाज ने दावा कि पिछले 10 सालों में जो प्राइवेट स्कूल माफिया खत्म हुआ था।

सच हो रही बाबा वेंगा की 2025 को लेकर डरावनी भविष्यवाणियां ! बताया कब होगा दुनिया का अंत

लंदन, एजेंसी। मशहूर बलोरियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की 2025 को लेकर की गई कुछ भविष्यवाणियां सच होती दिख रही हैं। हाल ही में म्यांमार में आए भीषण भूकंप में 2,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, और यह घटना उनकी उन भविष्यवाणियों से मेल खाती है, जिनमें उन्होंने विनाशकारी भूकंप की चेतावनी दी थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वेंगा ने इस विशेष भूकंप का उल्लेख किया था या नहीं, लेकिन इस त्रासदी के बाद उनकी भविष्यवाणियों को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के अनुसार, 2025 में दुनिया कई बड़े संकटों का सामना कर सकती है। कुछ प्रमुख चेतावनियां जो अब सच होती दिख रही हैं।

यूरोप में बड़े युद्ध की भविष्यवाणी: बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि 2025 में यूरोप एक बड़े युद्ध की चपेट में आएगा, जिससे महाद्वीप की जनसंख्या पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। मौजूदा रूस-यूक्रेन युद्ध और अन्य वैश्विक तनावों को देखते हुए, इस भविष्यवाणी को लेकर डर बढ़ रहा है। 2025 में वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता और आर्थिक पतन की भविष्यवाणी की गई थी। मौजूदा समय में दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी को देखते हुए, यह भविष्यवाणी भी सच होती दिख रही है। बाबा वेंगा ने 2025 को मानवता के पतन की शुरुआत के रूप में भी देखा था। अगर मौजूदा वैश्विक हालातों को देखा जाए-युद्ध, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट तो कई लोग इसे इस भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं।

पाकिस्तान में अफगान नागरिकों के खिलाफ एक्शन शुरू

सैकड़ों को पकड़ कर शिविरों में भेजा

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान सरकार ने अफगान नागरिकों के खिलाफ एक बड़ी राष्ट्रव्यापी कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत अफगान नागरिक कार्ड (एपीसी) धारकों सहित सैकड़ों अवैध विदेशियों को गिरफ्तार किया गया, और फिर उन्हें अफगानिस्तान वापस भेजने के लिए शिविरों में भेज दिया गया। पाकिस्तान में अफगान नागरिकों की स्वीच्छक वापसी के लिए निर्धारित 31 मार्च की समय-सीमा के बाद सैकड़ों अफगान नागरिकों को हिरासत में लिया गया

है और उनके परिवारों के साथ उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि सुरक्षा बलों को जारी निर्देशों से पता चलता है कि यदि कोई भी अफगान नागरिक आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो पूरे परिवार को निर्वासन का सामना करना पड़ेगा। काबुल में तालिबान सरकार ने इस्लामाबाद से पाकिस्तान में अफगान नागरिकों के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया में देरी का अनुरोध किया था, लेकिन इस्लामाबाद इसमें ढील देने के मूड में नहीं है। अफगान सरकार ने कहा, उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने नए सिरे से कार्रवाई की घोषणा



की है, जिसमें कहा गया कि वह बिना कानूनी निवास परमिट वाले विक्तियों को निर्वासित करेगा, जबकि वैध कार्डधारकों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में यूएनएचसीआर की प्रतिनिधि फिलिप कैडलर ने कहा, पाकिस्तान से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अनिश्चित काल तक अफगान शरणार्थियों की मेजबानी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए। मानवीय सहायता की जरूरत है, न केवल अल्पकालिक राहत के लिए बल्कि दीर्घकालिक विकास पहलों को समर्थन देने के लिए भी। समय सीमा को आगे न बढ़ाने

और कार्रवाई शुरू करने का निर्णय पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहम्मिन राजा नकवी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच हुई बैठक के दौरान लिया गया। सरकारी प्राधिकारियों ने कड़ी चेतावनी जारी की थी कि 31 मार्च तक देश नहीं छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत में अफगान शरणार्थियों को रखने के लिए कम से कम 43 शिविर स्थापित किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि अधिकारी छापेमारी करेंगे और देश में अवैध रूप से रह रहे अफगानों को हिरासत में लेंगे।

ईरान ने यमन में हूती विद्रोहियों को दिया बड़ा झटका, सैनिकों को बुलाया वापस

तेहरान। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के बढ़ते हमलों के बीच यमन के हूती विद्रोहियों को एक बड़ा झटका दिया है। ईरान की सरकार ने अपने सैन्य कमांडरों से कहा है कि वे तुरंत यमन छोड़ दें। इस कदम का उद्देश्य अमेरिका और इजरायल से सीधे टकराव से बचना है। इस स्थिति ने हूती विद्रोहियों को अकेला छोड़ दिया है और अब उन्हें बिना किसी बाहरी समर्थन के संघर्ष करना पड़ेगा। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने यह फैसला अमेरिकी हमलों के खोफ के कारण लिया है। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। इसके अलावा अमेरिकी परमाणु बॉम्बर बी-2 भी अब इस हमले में शामिल हो गए हैं। एक ईरानी अधिकारी के मुताबिक ईरान की सरकार ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को वापस बुलाने का फैसला इसलिए किया है ताकि वह अमेरिका से सीधे टकराव से बच सके। अमेरिका के इन हमलों में ईरान के एक सैनिक

की भी मौत हो गई है और इससे ईरान की क्षेत्रीय नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ईरान अब अपने समर्थक समूहों जैसे कि हमास, हूती और हिज्जुल्लाह से समर्थन कम कर रहा है ताकि वह अमेरिका से सीधे युद्ध में न उलझे। ईरान के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रंप प्रशासन के खिलाफ उनकी चिंता का मुख्य कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिनके खिलाफ ईरान के हर बैठक में चर्चा होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बार-बार चेतावनी दी है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम और हूती विद्रोहियों को दिए जाने वाले समर्थन को बंद करे। ट्रंप ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाते हुए दो परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के पास तैनात किया है और बड़े पैमाने पर बी-2 बॉम्बर को डिएगो गार्सिया में तैनात किया है। ट्रंप का कहना है कि यदि हूती विद्रोही ईरान के समर्थन से हफ्ला करते हैं तो इसे ईरान के खिलाफ हमला माना जाएगा।

